खंड: 8, अंक: 1 जनवरी 2025 RNI- DELHIN/2021/84711

ISSN- 2584-2803 (Print)

संश्लेषण

सी जी एस मासिक पत्रिका

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव एवं प्रभाव

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

दिल्ली विश्वविद्यालय

संपादक

प्रोफेसर सुनील कुमार

निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: director@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://cgs.du.ac.in/directorMessage.html

संपादक मंडल

डॉ रमेश कुमार भारद्वाज

सहायक आचार्य, सरकारी पी.जी कॉलेज, जीवाजी विश्वविद्यालय, श्योपुर पाली रोड, मध्य प्रदेश, पिन कोड-476337
संयुक्त निदेशक, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: rkbhardwaj1@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.mphighereducation.nic.in

डॉ महेश कौशिक

सहायक आचार्य, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, शिवालिक, मालवीय नगर, नई दिल्ली-110017
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: mkaushik@cgs.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://www.aurobindo.du.ac.in

डॉ संध्या वर्मा

एसोसिएट प्रोफेसर, श्यामलाल कॉलेज (सांध्य), दिल्ली विश्वविद्यालय, जी. टी. रोड, शाहदरा, दिल्ली-110032
अध्येता, वैश्विक अध्ययन शोध केंद्र (पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र, डीसीआरसी) एआरसी बिल्डिंग गुरु तेग बहादुर मार्ग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली-110007

ई-मेल आई डी: sverma@shyamlale.du.ac.in

प्रोफाइल लिंक: https://shyamlale.du.ac.in/wp-content/uploads/2021/11/sandhya-Verma-Political-Science.pdf

डॉ अभिषेक नाथ

सहायक आचार्य, एमएलटी कॉलेज, सहरसा; बी एन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा, बिहार।

ई-मेल आई डी: tuesdaytrack@gmail.com

प्रोफाइल लिंक: https://bpsm.bihar.gov.in/Assets2022/AssetDetails.aspx?P1=2&P2=12&P3=239&P4=3

© सीजीएस 2025

संश्लेषण

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव एवं प्रभाव

अनुक्रमिका

संपादकीय

1. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: मतदान व्यवहार और सत्ता परिवर्तन का एक विश्लेषण
– चंद्रिका आर्य 1–8
2. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: शासन बनाम लोकलुभावनवाद – नीलम 9–13
3. दिल्ली की राजनीतिक शतरंज की बिसातः विधानसभा चुनाव 2025 – प्रणय बरूआ 14–17
4. दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: चुनाव और उसके प्रभाव
– रहत रीत बराड़ और प्रांजल चौहान 18–23
5. दिल्ली विधानसभा चुनाव रुझान (1990–2025): राजनीतिक परिवर्तन व परिवर्तित मतदान व्यवहार तथा मतदाता भावनाओं की अंतदृष्टि – प्रशांत कुमार और सलोनी भाटी 24–29
6. दिल्ली विधानसभा 2025 : चुनाव एवं प्रभाव – सजल जैन 30–36
7. जलवायु परिवर्तन, निर्धनता व मुफ्त सुविधाएंः दिल्ली चुनाव के विषय
– प्रार्थना श्रीवास्तव और सिद्धार्थ 37–41

सम्पादकीय

निरंतरता, गुणवत्ता एवं महत्ता पर केन्द्रित सामरिक वाद–विषयों पर युवा शोधार्थियों से लेख आमंत्रण एवं प्रकाशन समसामयिक सामाजिक विज्ञान की एक महत्वपूर्ण चुनौती रहो है। प्रकाशन के इन महत्वपूर्ण सरोकारों और चुनौतियों के आलोक में वैश्विक अध्ययन केंद्र अपनी मासिक पत्रिका, संश्लेषण के 78वें अंक को पाठकों के समक्ष प्रेषित करते हुए अत्यंत हर्ष और उल्लास का अनुभव कर रहा है। आठ वर्षों से प्रकाशन की इस अकादमिक यात्रा में केंद्र एक परिवार के रुप में समस्त शोधार्थियों, शिक्षार्थियों एवं विद्यार्थियों के सामूहिक प्रयासों से सामाजिक विज्ञान के प्रति अपने संकल्पित ध्येय को साकार करता आ रहा है। निरंतरता की इस कडी में संश्लेषण का यह अंश शोध के प्रति हमारी प्रतिबद्धता एवं दृढ़निश्चतता को प्रदर्शित करने का ही एक सामान्य प्रयास है।

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटना बनने जा रहे हैं, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) के राजनीतिक परिदृश्य को नया आकार देने की क्षमता है। भारत की राजनीतिक व प्रशासनिक राजधानी होने के नाते, दिल्ली देश की चुनावी गतिशीलता में बहुत महत्व रखती है। आगामी चुनाव में मुख्य रूप से सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी (AAP), भारतीय जनता पार्टी (BJP) तथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मध्य महत्वपूर्ण स्पर्धा देखने को मिलेगी। अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में AAP अपनी सत्ता को सुदृढ़ करने की महत्वाकांक्षा क साथ 2025 के चुनावों में उतरेगी। पार्टी ने शासन सुधारों, खासकर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, जल आपूर्ति व बिजली के क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करके दिल्ली में एक मजबूत पकड़ बनाई है। AAP संभवतः अपनी कल्याणकारी योजनाओं के बल पर प्रचार करेगी, जिसने इसे शहर के मतदाताओं के मध्य पर्याप्त समर्थन दिलाया है। हाल के चुनावों में असफलताओं का सामना करने के बावजूद, भाजपा एक मजबूत दावेदार बनी हुई है। पार्टी की राष्ट्रीय उपस्थिति, साथ ही दिल्ली में इसका सुदृढ़ संगठनात्मक आधार, इसे AAP के प्रभुत्व को चुनौती देने की गति दे सकता है। भाजपा केंद्र सरकार की योजनाओं की लोकप्रियता और प्रधानमंत्री के साथ अपने राजनीतिक गठबंधन का लाभ उठाकर समर्थन प्राप्त कर सकती है।

कांग्रेस, जो कभी दिल्ली में एक प्रमुख शक्ति थी, अब अपनी प्रासंगिकता वापस पाने के लिए संघर्ष कर रही है। पार्टी की चुनौती एक ऐसा सुसंगत एजेंडा प्रस्तुत करना होगा जो शहर के विविध मतदाताओं को आकर्षित कर सके और स्वयं को AAP व BJP दोनों के लिए एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में स्थापित कर सके।

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव न केवल दिल्ली के राजनीतिक भविष्य का निर्णय करेंगे अपितु राष्ट्रीय राजनीतिक रुझानों को भी प्रभावित करेंगे। परिणामों का शासन, विकास व राजनीतिक विमर्श पर स्थायी प्रभाव पड़ने की संभावना है, जो राज्य व राष्ट्रीय राजनीति दोनों के भविष्य की दिशा को आकार देगा।

राष्ट्रीय स्तर पर विषय की महत्ता तथा राज्य स्तर पर विमर्श की समसामयिकता को ध्यान में रखते हुए केंद्र ने 'दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025ः चुनाव एवं प्रभाव' विषय पर लेख आमंत्रित किये। पाँच उत्कृष्ट लेखों को सम्पादकीय मंडल ने चयनित किया जो आप सभी के समक्ष एक प्रकाशित पत्रिका के रूप में उल्लेखित हो रहे हैं। ये समस्त लेख मौलिक होने के साथ–साथ भारत के लोकतांत्रिक परिदृश्य के बहुआयामी विषयों को भी संबोधित करते हैं। स्वतंत्र चिंतन पर आधारित लेखकों के विचार उनकी रचनात्मकता, सृजनात्मकता एवं मौलिकता को प्रदृशित करने का एक सर्वनिष्ठ प्रयास, प्रयत्न और परिणाम है।

संपादक मंडल शुक्रवार, 14 फरवरी 2025

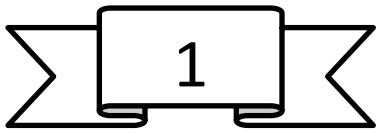

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025ः मतदान व्यवहार और सत्ता परिवर्तन का एक विश्लेषण

चंद्रिका आर्य

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

पिछले एक दशक से दिल्ली के मतदाताओं का मतदान व्यवहार लोकसभा चुनावों और विधानसभा चुनावों में अलग अलग रहा है जैसे लोकसभा में राष्ट्रीय मुद्दों और मोदी के नेतृत्व से प्रभावित होकर वहीं विधानसभा में स्थानीय मुद्दों और विकास के नाम पर मतदान हुआ है। उदाहरण के रूप में यदि 2014 लोकसभा चुनावों की बात करें तो भाजपा के पक्ष में 46.4% मतदान हुआ वहीं आप और कांग्रेस के पक्ष में यह क्रमशः 32.9% और 15.1% था। परंतु लोकसभा चुनाव के आठ महीने बाद हुए दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा का वोट शेयर लगभग 14 प्वाइंट नीचे आ गया और पार्टी को केवल 32.2% वोट ही प्राप्त हुए, वहीं कांग्रेस में यह गिरावट लगभग 6 प्वाइंट की थी और उन्हें केवल 9.7% से संतोष करना पड़ा परंतु दूसरी तरफ लगभग 22 प्वाइंट की बढ़ोतरी के साथ 54.5% वोट पाकर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के इतिहास की सबसे बड़ी जीत दर्ज करने में सफलता हासिल की।

ऐसे ही 2019 लोकसभा चुनावों में देखने को मिला जब भाजपा को 56.8%, कांग्रेस को 22.5% और आप को केवल 18.1% वोट प्राप्त हुए परंतु वहीं आठ महीने बाद हुए विधानसभा चुनावों में भाजपा और कांग्रेस का वोट शेयर लगभग 18 प्वाइंट की गिरावट के साथ क्रमशः 38.7% और 4.3% रह गया और आप का लगभग 35 प्वाइंट की बढ़ोतरी के साथ 53.8ः पर जा पहुंचा और इसके सहारे एक बार फिर आप ने दिल्ली में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की।

परंतु 2025 में यह ट्रेंड बदल गया और इस बार विधानसभा में भी लोकसभा के मुकाबले बहुत बड़े स्तर पर वोट स्विंग नहीं हुआ जिसका फायद भाजपा को और नुकसान आप को हुआ, जैसे 2024

लोकसभा चुनावों में भाजपा को 54.35%, कांग्रेस को 18.91% और आप को 24.17% वोट मिले, वहीं विधानसभा चुनावों में भाजपा केवल 9 प्वाइंट की गिरावट के साथ 45.56ः वोट प्राप्त करने में कामयाब हुई और कांग्रेस को 12 प्वाइंट का नुकसान हुआ जबकि आप 19 प्वाइंट की बढ़ोतरी ही कर पाई, जो पिछले दोनों विधानसभा चुनावों से कम है।

इस बार भी आम आदमी पार्टी इसी उम्मीद में थी कि दिल्ली के मतदाता विधानसभा चुनावों में लोकसभा के मुकाबले आप के पक्ष में अधिक मतदान करेंगे परंतु भाजपा ने अपनी कड़ी मेहनत से इसे होने से रोक लिया और ढाई दशकों से भी ज्यादा समय के बाद राष्ट्रीय राजधानी में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल की। यह लेख दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा कैसे मतदाताओं को अपने पाले में रख पाई और आप कैसे पिछड़ती गई, के साथ साथ कांग्रेस की शून्य हैट्रिक और भाजपा की नवनिर्मित सरकार के समक्ष चुनौतियां का विश्लेषण करेगा।

(क.) भाजपा द्वारा मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के मुख्य कारण

1.) विश्वास का मुद्दा –

भाजपा ने अपनी चुनावी घोषणाओं के माध्यम से दिल्ली के मतदाताओं का विश्वास जीतने में सफलता हासिल की। केजरीवाल की गारंटी के सामने आम मतदाता ने भाजपा द्वारा पेश की गई ष्मोदी की गारंटीष् पर भरोसा जताया। भाजपा 2020 विधानसभा चुनावों के बाद से ही दिल्ली के मतदाताओं का भरोसा जीतने की कोशिश में लगी हुई थी। जैसे बात चाहे कोविड के दौरान लगे लॉकडाउन की करें तब भी भाजपा के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़ कर दिल्ली वासियों को सुविधाएं उपलब्ध करवाने में अपना योगदान दिया, इसके अलावा 2020 से ही भाजपा ने आप सरकार की कमियों को उजागर करने का काम बड़े प्रभावशाली तरीके से किया और भाजपा ने बिना कोई मौका चुके पूरे कार्यकाल में आप सरकार को कटघरे में खड़ा करने का सफल प्रयास किया और दिल्ली के मतदाताओं से अपना जुड़ाव टूटने नहीं दिया जिसके परिणाम स्वरूप दिल्ली के मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान करके इनकी मेहनत का फल इन्हें दिया।

2.) चुनाव प्रचार –

भाजपा चुनाव के शुरुआती दौर में आप से कड़ी चुनौती का सामना कर रही थी परंतु जैसे जैसे भाजपा ने अपने चुनाव प्रचार को गति दी वैसे वैसे आप के मुकाबले ज्यादा मजबूत होती गई। इस बार चुनाव में भाजपा ने कोई स्थानीय नेता को चेहरा बनाने की बजाय (जैसे 2015 में किरण बेदी और 2020 में मनोज तिवारी को मुख्य चेहरा बनाया था) पूरा चुनाव हर तरीके से मोदी के

नाम पर लड़ा। चुनावी दिन आते आते चुनाव मोदी बनाम केजरीवाल हो गया और पिछले एक दशक की ये सच्चाई है कि मोदी के सामने कोई भी नेता सफल नहीं हो पाया है, जहां जहां भाजपा ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा है वहां लगातार सफतला दर्ज की है जैसे हाल ही में हरियाणा का उदाहरण इसका पुख्ता सबूत है जहां हर कोई टीवी चौनल, राजनीतिक विश्लेषक ये मान कर बैठा था कि कांग्रेस आसानी से चुनाव जीत जाएगी परंतु भाजपा ने मोदी के नाम पर चुनाव लड़ा और चुनावी नतीजे के दिन प्रदेश में अपनी सबसे बड़ी जीत पर मुहर लगा पाने में सफल हुई। अर्थात मोदी के नाम पर सफलता की मुहर है। इसके साथ ही भाजपा ने दिल्ली में बहुत गहनता से चुनाव प्रचार करते हुए दिल्ली के प्रत्येक दरवाजे तक पहुंचने की सफल कोशिश की जैसे यदि दिल्ली में आंध्र प्रदेश से आकर बसे लोगों की एक ही कॉलोनी थी तो उसमें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्र बाबू नायडू की छोटी छोटी सभाएं करवाई जिससे वो मतदाता आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के कहने से भाजपा के पक्ष में मतदान करने को राजी हुए, ऐसे ही प्रत्येक समुदाय, प्रत्येक जाति, प्रत्येक धर्म, प्रत्येक समूह को ध्यान में रख कर उनके सबसे बड़े नेताओं को गली गली घुमाया और उनसे भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील करवाई जिसका परिणाम 8 फरवरी को देखने को मिला।

3.) स्विंग मतदाताओं को स्थिर करने में सफलता –

पिछले एक दशक से दिल्ली के लगभग 18 से 20 फीसदी मतदाता लोकसभा और विधानसभा चुनाव में स्विंग हो रहे थे। लोकसभा में वो भाजपा के पक्ष में वहीं विधानसभा में भाजपा के विपक्ष में और आप के पक्ष में मतदान कर रहे थे परंतु भाजपा ने इस बार अपनी रणनीति और कड़ी मेहनत से बड़े स्तर पर स्विंग होने वाले इस मतदाता समूह को स्थिर करने में सफलता हासिल की जिससे इस बार भाजपा को लोकसभा के मुकाबले वोट शेयर में ज्यादा गिरावट नहीं झेलनी पड़ी।

(ख.) आम आदमी पार्टी दिल्ली के मतदाताओं के दिल से कैसे उतरी

1.) भ्रष्टाचार –

आम आदमी पार्टी का जन्म भ्रष्टाचार के खिलाफ इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन के दौरान हुआ परंतु एक दशक बीतते बीतते आम आदमी पार्टी खुद ही भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई और अपनी ईमानदार छवि के चलते पार्टी व इसके नेताओं ने जो आम मतदाताओं का भरोसा जीता था उसे गवां दिया। पार्टी के शीर्ष नेता लगभग पिछले तीन वर्षों से भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में तिहाड़

जेल की हवा खा रहे हैं इससे पार्टी न तो दिल्ली में कुछ विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर पाई और न ही अपनी छवि बचा पाई। इसके अलावा पार्टी के शीर्ष नेता अरविंद केजरीवाल का एक दशक पहले के बयानों और आज के ऐशो आराम से दिल्ली के मतदाताओं का उनसे भरोसा टूटा है। एक दशक पहले केजरीवाल चिल्ला चिल्ला कर कहते थे कि उन्हें सीएम की कुर्सी से कोई लगाव नहीं है, परंतु पिछले वर्ष पूरे समय जब वो जेल में रहे तो भी इस्तीफा नहीं दिया और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर किसी को नहीं बैठने दिया। सीएम बनने से पहले केजरीवाल का कहना था कि वो सरकारी आवास में नहीं रहेंगे परंतु 30 करोड़ से भी ज्यादा लागत से अपने लिए शीश महल का निर्माण कर लिया आदि ऐसी अनेक घटनाएं घटित हुई जिनके सम्बन्ध में एक दशक पहले केजरीवाल के विचार बिल्कुल अलग थे, इससे केजरीवाल की छवि में भारी गिरावट आई है। अब उनका अन्य नेताओं से वो अंतर भी खत्म हो गया जो शुरुआती दौर में उन्होंने स्थापित किया था।

2.) विकास और नए वादों का अभाव –

वर्ष 2015 में दिल्ली के मतदाताओं ने दिल्ली के विकास और ईमानदार सरकार की उम्मीद में आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी संख्या में मतदान किया और केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी ने जैसे सरकारी स्कूलों का कायापलट, पानी की सुविधा, मुफ्त बिजली, मोहल्ला क्लिनिक इत्यादि बड़े कार्य करके दिल्ली वासियों की उम्मीदों पर खरा उतरने में सफलता भी हासिल की और केजरीवाल के इसी सफल कार्यकाल का नतीजा था कि वर्ष 2020 में एक बार फिर दिल्ली वासियों ने आम आदमी पार्टी के पक्ष में भारी संख्या मतदान किया और आप की दूसरी बार ऐतिहासिक सरकार बनाने में अपना योगदान दर्ज करवाया परंतु अपने दूसरे कार्यकाल में पार्टी विकास और अपने चुनावी मुद्दों को आम मतदाता तक नहीं पहुंचा पाई। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण था केजरीवाल सहित पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में जेल चले जाना। पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के जेल में रहते किसी दूसरे नेता को जिम्मेदारी नहीं देना भी पार्टी के लिए नुकसानदायक साबित हुआ। इसके अलावा इस चुनाव में आप के पास चुनाव जीतने के लिए न तो नए वादे थे और न ही विकास के कोई कीर्तिमान। पार्टी के पास था तो केवल भ्रष्टाचार और उसमें लिप्त उनका शीर्ष नेतृत्व।

3.) एंटी इनकंबेंसी –

एक दशक से सरकार चला रहे केजरीवाल के सामने एंटी इनकंबेंसी भी एक अहम मसला था जिसे पार्टी पार करने में असफल रही है क्योंकि इसे केवल नए वादों और किए गए विकास कार्यों से

ही भुनाया जा सकता है परंतु आप अपने अति आत्मविश्वास के चलते इसे नहीं कर पाई। वहीं भाजपा ने चुनाव के 4 दिन पहले केंद्रीय बजट के माध्यम से आमजन को टैक्स में जो छूट दी वो अपने आप में पार्टी का मास्टर स्ट्रोक था, जिसने दिल्लीवासियों को नई आशा प्रदान की। इन सबके अलावा प्रदूषण पर, यमुना नदी की सफाई न करने पर, भ्रष्टाचार से अपना अलगाव न कर पाने के कारण और सत्ता को न त्यागने जैसे अनेकों कारणों से आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में मुंह की खानी पड़ी है।

(ग.) कांग्रेस की जीरो की हैट्रिक के पीछे मुख्य कारण

1.) चुनाव लड़ने की अनिच्छा –

असल में कांग्रेस पार्टी ने बिना तैयारी के चुनाव लड़ने शुरू कर दिए हैं, 2013 के बाद से बसपा की तरह कांग्रेस चुनावी मैदान में अपने उम्मीदवार तो उतारती है परंतु जीतने की अनिच्छा से। पार्टी ने पिछले 12 वर्षों में ऐसा कोई प्रयास चुनावों के दौरान या चुनावों से पहले नहीं किया जिससे लगे कि कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने और जीतने के लिए उत्साहित है।

2.) बिना नेता की कांग्रेस –

शीला दीक्षित के मुख्यमंत्री रहते कांग्रेस ने दिल्ली में दूसरी पीढ़ी का कोई नेता पैदा नहीं किया, कुछ जो बन सकते थे उन्हें पार्टी अपने पाले में रख पाने में विफल रही है। इसके अलावा मौजूदा समय में जब सामने मोदी – केजरीवाल जैसा नेता हो तो निश्चित रूप से कांग्रेस की भी उनके मुकाबले का नेता चुनाव में उतारना होगा और पूरी योजना और रणनीति के तहत चुनाव लड़ना होगा तभी ये जीरो का सिलसिला टूट सकता है।

3.) रणनीति का अभाव–

कांग्रेस के पास दिल्ली में लागू करने हेतु न तो कोई जनकल्याणकारी योजनाएं हैं और न ही विकास का कोई रोडमैप। पार्टी दिल्ली के मतदाताओं तक ना तो अभी तक ये तथ्य पहुंचा पाई है कि शीला दीक्षित के नेतृत्व में कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में विकास के वो सब कार्य किए जो उस समय किए जाने आवश्यक थे और ना ही कोई विकल्प पेश कर पाई है। यही मुख्य कारण है कि पिछले तीन चुनावों में पार्टी लगातार जीरो पर सिमट कर रह गई है।

(घ.) भाजपा की नवनिर्मित सरकार के समक्ष चुनौतियां

दिल्ली में भाजपा सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण पर लगाम कसना, इसमें वायु प्रदूषण के साथ साथ जल प्रदूषण और यमुना नदी की सफाई करना सबसे महत्वपूर्ण है। चूंकि अब दिल्ली के साथ साथ इससे सटे हुए उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा तीनों राज्यों में भाजपा की सरकार है और केंद्र में भी भाजपा सत्तारूढ़ है इसलिए अब पिछली सरकारों की तरह पड़ोसी राज्यों पर आरोप प्रत्यारोप लगाकर अपना बचाव करना संभव नहीं है क्योंकि अब ऐसा किसी भी प्रकार का कोई बहाना नहीं चलेगा। इसके अलावा अब भाजपा के सामने दिल्ली वासियों को पिछले एक दशक से मिल रही फ्रीबीज को चालू रखना भी बड़ी चुनौती होगा क्योंकि यदि इन्हें चालू रखा जाएगा तो निश्चित रूप से विकास की गति धीमी रहेगी और यदि ऐसा होता है तो बीजेपी के लिए भविष्य में कठिनाइयां बढ़ेगी। इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक में सुधार, सरकारी स्कूलों को और आगे लेकर जाना, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और महिलाओं की मुफ्त बस यात्रा को चालू रखना आदि बड़ी चुनौतियों के साथ दिल्ली में भाजपा की डबल इंजन की सरकार के लिए भविष्य का रास्ता फूलों की सेज नहीं बल्कि कांटो भरा है।

निष्कर्ष – उपरोक्त विश्लेषण से साफ है कि दिल्ली के मतदाताओं ने विकास की उम्मीद और आशा में आम आदमी पार्टी की बजाय भाजपा के पक्ष में मतदान किया है परंतु अब आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि कैसे भाजपा अपने समक्ष मुंह बाय खड़ी बड़ी चुनौतियों से पार पाते हुए दिल्ली वासियों की उम्मीदों को पूरा कर पाएगी।

संदर्भ सूची

- Atal, Y. & Choudhary S.K. (2015). Right Turn in Indian Polity. Har-Anand Publications Pvt. Ltd.
- Babu, N. Aam Aadami Party: The common party. February 16, 2025. The Hindu. https://www.thehindu.com/elections/delhi-assembly/aam-aadmi-party-the-common-party/article69223879.ece
- Banerjee, M. (2014). Why India Votes. New Delhi: Routledge.
- Deshmukh, Y. Delhi elections- A masterclass in strategy by team Modi. February 11, 2025.
- Mishra, J. What moved Delhi voters. February 10, 2025. The Indian Express.
- Mishra, S. BJP has finally won Delhi but for AAP, the battle may just have begun, February 09 2025. The Hindu.
- Povaiah, R. Five reasons why AAP have lost Delhi- a voter's perspective, February 08, 2025. Financial Express.
- Saxena, R. (2019). The Indian National Congress: Coping with Challenges of deepening Democracy, Federalism and Neoliberal Capitalism. In Kumar, A. And Sisodia, Y(eds.), How India Votes: A State-by-state Look. (2019). New Delhi: Orient Black Swan.
- Tanan, S. The perception shift against the AAP in the Delhi election, February 20, 2025. The Hindu.
- Wallace, P. (2015). India's 2014 Elections: A Modi - led BJP Sweep. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd.

- Wallace, P. (2020). India's 2019 Elections: The Hindutva wave and Indian Nationalism. New Delhi: Sage Publications India Pvt. Ltd.

♦♦♦♦♦

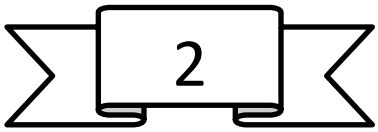

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: शासन बनाम लोकलुभावनवाद

नीलम

शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

भारत की राजधानी दिल्ली ने पिछले कुछ दशकों में एक आकर्षक राजनीतिक प्रक्षेपवक्र देखा है। दिल्ली में चुनाव केवल स्थानीय नेताओं को चुनने के बारे में नहीं हैं, बल्कि वे बड़े राजनीतिक आख्यानों को दर्शाते हैं, जो अक्सर शासन बनाम लोकलुभावनवाद के इर्द–गिर्द केंद्रित होते हैं। दिल्ली में दो प्रमुख राजनीतिक ताकतोंरू आम आदमी पार्टी (आप) और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनावी रणनीतियों का विश्लेषण करने पर यह विरोधाभास और भी स्पष्ट हो जाता है। आप, जो पारंपरिक राजनीति से अलग हटकर काम करने का वादा करके प्रमुखता में आई, शासन और जमीनी स्तर पर जुड़ाव की हिमायती है, जबकि भाजपा राष्ट्रवादी बयानबाजी और लोकलुभावन उपायों पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है। दिल्ली चुनाव में शासन और लोकलुभावनवाद के बीच का अंतर भारत में लोकतंत्र और राजनीतिक रणनीतियों के भविष्य के बारे में महत्वपूर्ण सवाल उठाता है।

आम आदमी पार्टी का उदयः नींव के रूप में शासन

आम आदमी पार्टी (आप) 2013 में एक राजनीतिक ताकत के रूप में उभरी, जिसका नेतृत्व अरविंद केजरीवाल ने किया, जो एक पूर्व सिविल सेवक थे, जिन्होंने भारत के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन में अपनी भूमिका के लिए राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया था। पारंपरिक पार्टियों के विपरीत, जो अक्सर लोकलुभावनवाद पर निर्भर रहती थीं, AAP ने खुद को शासन सुधार, पारदर्शिता और स्थानीय मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित पार्टी के रूप में स्थापित किया, जो सीधे दिल्ली के नागरिकों को प्रभावित करते हैं। केजरीवाल का शासन–केंद्रित एजेंडा शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और पानी और बिजली जैसी आवश्यक नागरिक सेवाओं को बेहतर बनाने के पार्टी के वादे में स्पष्ट है। AAP के नेतृत्व में दिल्ली सरकार ने सब्सिडी वाले पानी और बिजली उपलब्ध कराने, सरकारी स्कूलों में सुधार करने और मोहल्ला क्लीनिकों की शुरुआत के साथ स्वास्थ्य सेवा में सुधार शुरू

करने में महत्वपूर्ण प्रगति की। इस दृष्टिकोण को पारंपरिक राजनीतिक प्रतिष्ठानों के भीतर कथित अक्षमताओं और भ्रष्टाचार के प्रत्यक्ष जवाब के रूप में देखा गया है। AAP का शासन मॉडल ष्नीचे से सशक्तिकरण के विचार पर बनाया गया है। जमीनी स्तर पर जुड़ाव पर ध्यान केंद्रित करके, AAP नेताओं ने नागरिकों से सीधे जुड़ने, उनकी शिकायतों को सुनने और स्थानीय समाधानों के साथ उनका समाधान करने की कोशिश की है। शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा सुधारों पर पार्टी के जोर ने, विशेष रूप से राजधानी में, शहरी मध्यम वर्ग और समाज के हाशिए पर पड़े वर्गों से महत्वपूर्ण समर्थन प्राप्त किया। शासन के संदर्भ में, AAP ने भ्रष्टाचार को कम करने, प्रशासनिक नियंत्रण को विकेंद्रीकृत करने और दक्षता को बढ़ावा देने के लिए भी कदम उठाए हैं। यह लोकलुभावनवाद के पारंपरिक मॉडल के बिल्कुल विपरीत है, जहाँ उपाय अल्पावधि में लोकप्रिय हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकालिक स्थिरता की कमी हो सकती है।

दिल्ली में लोकलुभावनवादः भाजपा की राष्ट्रीय रणनीति

शासन पर AAP के फोकस के विपरीत, भाजपा ने ऐतिहासिक रूप से लोकलुभावन उपायों पर भरोसा किया है जो व्यापक राष्ट्रीय भावनाओं को छूते हैं। दिल्ली में भाजपा की राजनीतिक रणनीति, विशेष रूप से चुनाव के समय, अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा, हिंदू पहचान और हिंदू सांस्कृतिक मूल्यों क उत्सव के मुद्दों पर केंद्रित रही है। पार्टी ने मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए अक्सर लोकलुभावन बयानबाजी का इस्तेमाल किया है, जो अक्सर स्थानीय शासन के मुद्दों पर हावी हो जाता है।

लोकलुभावनवाद के प्रति भाजपा के दृष्टिकोण में भावनात्मक अभियानों का उपयोग शामिल है, जैसे मंदिर बनाने का वादा, हिंदू मतदाताओं की चिंताओं को दूर करना और पाकिस्तान, मुसलमानों या अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से कथित खतरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करना। इन राष्ट्रवादी आख्यानों का उपयोग मतदाताओं के बीच तत्परता और एकजुटता की भावना पैदा करने के लिए किया गया है। साथ ही, वे अक्सर शासन, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसे मुद्दों से ध्यान हटाते हैं, जिन्हें स्थानीय और व्यावहारिक चिंताएँ माना जाता है।

राष्ट्रवादी बयानबाजी के अलावा, भाजपा आर्थिक विकास के लोकलुभावन वादों पर भी निर्भर करती है। उनका अभियान रोजगार सृजन, बुनियादी ढाँचे में सुधार और ष्सबका साथ, सबका विकासष को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। हालाँकि, ये वादे मतदाताओं को आकर्षित करते हैं, लेकिन अक्सर अस्पष्ट होने और दिल्ली के निवासियों के सामने आने वाली दिन–प्रतिदिन की शासन चुनौतियों को संबोधित नहीं करने के लिए आलोचना की जाती है।

जबकि AAP का ध्यान मुख्य रूप से दैनिक जीवन में ठोस सुधार पर है, भाजपा अक्सर बड़े–से–बड़े वादों और राष्ट्रवादी विषयों पर निर्भर करती है। यह लोकलुभावन दृष्टिकोण दिल्ली के मतदाताओं के एक महत्वपूर्ण हिस्से, विशेष रूप से शहरी कामकाजी वर्ग और मध्यम वर्ग के वर्गों के साथ तालमेल बिठाने में कामयाब रहा है, जो राष्ट्रवाद और सुरक्षा जैसे व्यापक राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित हैं।

दिल्ली के चुनावी परिदृश्य पर प्रभाव

दिल्ली में चुनावी परिदृश्य को शासन और लोकलुभावनवाद के बीच तनाव द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। स्थानीय स्तर पर बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और बुनियादी ढाँचे जैसे ठोस परिणाम देने में AAP की सफलता ने इसे एक दुर्जेय शक्ति बना दिया है। पार्टी ने लगातार मतदाताओं का विश्वास जीता है जो सुशासन, पारदर्शिता और कुशल प्रशासन को प्राथमिकता देते हैं। वास्तव में, दिल्ली विधानसभा चुनावों में AAP का प्रभावशाली प्रदर्शन, जहाँ इसने कई चुनावों में पर्याप्त बहुमत हासिल किया है, मतदाताओं की शासन–उन्मुख राजनीति के लिए प्राथमिकता को रेखांकित करता है।

दूसरी ओर, भाजपा की लोकलुभावन बयानबाजी मतदाताओं के एक वर्ग को प्रभावित करती रहती है, विशेष रूप से वे जो राष्ट्रीय मुद्दों से प्रभावित होते हैं या जिन्हें लगता है कि हिंदू पहचान और राष्ट्रीय सुरक्षा के बारे में उनकी चिंताओं को AAP द्वारा पर्याप्त रूप से संबोधित नहीं किया जाता है। राष्ट्रवाद और पहचान की राजनीति के इर्द–गिर्द एक बड़ा आख्यान बनाने की भाजपा की रणनीति दिल्ली में राजनीतिक विमर्श को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहती है।

2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव इस बात का स्पष्ट उदाहरण थे कि शासन और लोकलुभावनवाद के बीच प्रतिस्पर्धा कैसे होती है। AAP ने अपने अभियान को स्थानीय मुद्दों पर केंद्रित किया, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अपनी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण दिया, जबकि भाजपा ने अनुच्छेद 370 CAA (नागरिकता संशोधन अधिनियम) और आतंकवाद पर अपने रुख जैसे राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में चुनाव लड़ा। इसका नतीजा AAP के लिए निर्णायक जीत थी, जिसमें पार्टी ने 70 में से 62 सीटें जीतीं, जो लोकलुभावन कथाओं पर सुशासन के लिए स्पष्ट जनादेश था।

शासन और दिल्ली चुनाव का भविष्य आगे देखते हुए, दिल्ली में शासन और लोकलुभावनवाद के बीच की लड़ाई खत्म होने की संभावना नहीं है। जब तक AAP सेवाओं को बेहतर बनाने और

स्थानीय आबादी की जरूरतों को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करती है, तब तक दिल्ली के शहरी और अर्ध–शहरी निर्वाचन क्षेत्रों में इसका प्रदर्शन अच्छा रहने की संभावना है। साथ ही, भाजपा की लोकलुभावन अपील एक महत्वपूर्ण कारक बनी रहने की संभावना है, खासकर राष्ट्रीय या राज्य–स्तरीय अभियानों के दौरान जो व्यापक राजनीतिक माहौल से जुड़े होते हैं।

एक तरह से, दिल्ली के चुनाव शासन और लोकलुभावनवाद के बीच बड़ी राष्ट्रीय राजनीतिक लड़ाई का एक सूक्ष्म रूप हैं। जहाँ AAP स्थानीय मुद्दों के व्यावहारिक समाधानों पर ध्यान केंद्रित करती है, वहीं भाजपा एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है, जो मतदाताओं की भावनाओं और पहचान की भावना को आकर्षित करने के लिए लोकलुभावन रणनीतियों का लाभ उठाती है। इन दो दृष्टिकोणों के बीच संतुलन संभवतः दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य और, विस्तार से, भारत के लोकतंत्र के भविष्य को आकार देगा।

निष्कर्ष

दिल्ली के चुनावों ने आधुनिक भारतीय राजनीति में शासन और लोकलुभावनवाद के बीच बढ़ते तनाव को उजागर किया है। AAP के शासन और पारदर्शिता पर जोर ने इसे उन लोगों के बीच एक मजबूत आधार बनाने की अनुमति दी है जो अपने दैनिक जीवन में व्यावहारिक, जमीनी सुधारों को प्राथमिकता देते हैं। इस बीच, राष्ट्रीय मुद्दों और पहचान की राजनीति में निहित भाजपा की लोकलुभावन अपील चुनावी बहस को आकार देने में एक शक्तिशाली शक्ति बनी हुई है। अंततः, दिल्ली के चुनावों के परिणाम भारत में व्यापक राजनीतिक गतिशीलता में मूल्यवान अंतदृष्टि प्रदान करते हैं और एक झलक प्रदान करते हैं कि चुनावी राजनीति तेजी से ध्रुवीकृत वातावरण में कैसे विकसित हो रही है।

संदर्भ सूची

- "Arvind Kejriwal’s Education Revolution: How AAP's Focus on Governance Helped Win Delhi," *The Hindu*, February 2020.
- Delhi Assembly Election Results 2020: AAP Sweeps Delhi, BJP's National Agenda Fails," *The Economic Times*, February 2020.
- "Populism in India: The Rise of Nationalism and Identity Politics," *India Today*, April 2020.
- "The BJP’s Nationalist Agenda: Implications for Delhi Elections," *Mint*, January 2020.

♦♦♦♦♦

3

दिल्ली की राजनीतिक शतरंज की बिसातः विधानसभा चुनाव 2025

प्रणय बरूआ

एम.ए., विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव एक राजनीतिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण घटना के रूप में सामने आए। यह चुनाव न केवल त्रिकोणीय संघर्ष का प्रतीक था, बल्कि इसने दिल्ली की राजनीति में व्यापक बदलाव और जनमत की विभिन्न धाराओं को भी उजागर किया। इस चुनाव में तीन प्रमुख राजनीतिक दलों– आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपनी–अपनी नीतियों और विकासात्मक दृष्टिकोणों के साथ मुकाबला किया। इन चुनावों ने देशभर में विभिन्न मुद्दों के बीच प्रतिस्पर्धा को उजागर किया, जिनमें मुफ्त सुविधाओं, बुनियादी ढांचे के विकास, भ्रष्टाचार, प्रदूषण, यमुनाजी की सफाई, कानून और व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे प्रमुख थे। जबकि एग्जिट पोल्स ने कड़ा मुकाबला और कई जगहों पर विधानसभा में त्रिशंकु सभा की संभावना जताई थी, वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से काफी भिन्न रहे। भाजपा ने 70 सीटों में से 48 सीटें जीतकर दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में वापसी की, जिससे यह चुनाव इतिहास में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ।

चुनाव परिणामों से परे, इस चुनाव के दौरान हुई घटनाओं, प्रचार, और मतदाता की प्रवृत्तियों का विश्लेषण कई महत्वपूर्ण निष्कर्षों की ओर इशारा करता है। इन चुनावों में उत्तर–पूर्व दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों में राजनीतिक जागरूकता और मतदाताओं के बीच उत्साह की कोई कमी नहीं थी। अधिकांश मतदाता इन चुनावों को केवल एक पार्टी और उसकी विचारधारा के परिप्रेक्ष्य से देख रहे थे, जबकि कुछ ने इसे एक व्यक्ति के करिश्मा और कार्यक्षमता के नजरिए से देखा। इसके अतिरिक्त, कुछ मतदाता राजनीतिक दलों के घोषणापत्रों में उठाए गए विशिष्ट मुद्दों को भी प्रमुखता से देख रहे थे। इस चुनाव ने यह साबित किया कि चुनावी संघर्ष हमेशा मुद्दों के आधार पर लड़ा जाता है। इस चुनाव में यह तथ्य विशेष रूप से स्पष्ट हुआ।

विभिन्न मुद्दों ने चुनावी भागीदारी को प्रभावित किया, जैसे मुफ्त बिजली और पानी की आपूर्ति, शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, सफाई, प्रदूषण, यमुनाजी की सफाई, कानून और व्यवस्था, और

विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण की दिशा में वित्तीय सहायता योजनाएँ, जैसे कि महिला सम्मान योजना। इस चुनाव में सबसे अधिक चर्चा का विषय मुफ्त सुविधाओं या रेवड़ी की राजनीति बनी। आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने इन मुफ्त सुविधाओं को श्रेवड़ी' कहा और दिल्लीवासियों को छह श्रवड़ीश देने का वादा किया, जिसमें मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा, मोहल्ला क्लिनिक, महिलाओं के लिए बस यात्रा, और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा शामिल थी। उन्होंने यह भी वादा किया कि यदि पार्टी सत्ता में आई तो महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। अन्य पार्टियों, विशेषकर भाजपा ने मुफ्त सुविधाओं की संस्कृति के खिलाफ विरोध किया, लेकिन जल्द ही उन्होंने महसूस किया कि इस चुनावी समर में उन्हें भी उसी पानी में तैरना पड़ेगा। भाजपा और कांग्रेस दोनों ने महिलाओं के लिए 2500 रुपये की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, जो इस बात को साबित करता है कि आजकल महिला मतदाता कितना प्रभावी और निर्णायक हो चुका है।

इन मुफ्त योजनाओं को गरीबों के लिए सामाजिक कल्याण और सशक्तिकरण के रूप में सराहा गया, लेकिन उच्च मध्यवर्ग और संपन्न वर्ग ने इन नीतियों पर आपत्ति जताई, उनका मानना था कि ये योजनाएँ लोगों में आलसी प्रवृत्तियों को बढ़ावा देती हैं और दिल्ली की अर्थव्यवस्था को कमजोर करती हैं। इसके अतिरिक्त, एक और प्रमुख मुद्दा जो चुनावी चर्चा में था, वह था अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के आरोप। भाजपा ने इस मुद्दे को अपनी चुनावी रणनीति का प्रमुख हिस्सा बनाया, ताकि दिल्ली के मतदाताओं में समर्थन जुटाया जा सके। भाजपा ने आराप लगाया कि आम आदमी पार्टी ने प्रदूषण कम करने और यमुनाजी की सफाई को लेकर पर्याप्त कदम नहीं उठाए, और ये मुद्दे दिल्ली के विभिन्न मतदाताओं में गूंजते रहे, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जो प्रदूषण और पर्यावरणीय समस्याओं से जूझ रहे थे।

उत्तर–पूर्व दिल्ली के मतदाताओं के बीच अव्यवस्थित जल निकासी सुविधाएं और सफाई की समस्याएं भी चुनाव के प्रमुख मुद्दे बने। विशेष रूप से बाबरपुर, सीलमपुर, मुस्तफाबाद जैसे क्षेत्रों में, स्थानीय लोग कानून–व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति और बढ़ते अपराधों से परेशान थे। 2020 के उत्तर–पूर्व दिल्ली दंगों के बाद से इन क्षेत्रों में अपराधों में वृद्धि देखी गई थी, और यह मुद्दा चुनावी प्रचार में एक महत्वपूर्ण बिंदु बना। भाजपा ने अपनी चुनावी रणनीति में इस मुद्दे को प्रमुख रूप से उठाया और अपने समर्थकों को आश्वस्त किया कि वे कान्न–व्यवस्था सुधारने के लिए ठोस कदम उठाएंगे। इसी तरह, दिल्ली के झुग्गी बस्ती क्षेत्रों में निवासियों के लिए सरकार की योजनाओं और स्लम विकास को लेकर भी एक बड़ा सवाल था।

महिला मतदाताओं, युवा मतदाताओं और अल्पसंख्यक मतदाताओं के दृष्टिकोण से इस चुनाव का विश्लेषण कई रोचक पहलुओं को उजागर करता है। जबकि तीनों प्रमुख दलों ने महिलाओं को वित्तीय सहायता देने का वादा किया, अधिकांश महिलाओं का मानना था कि केवल आम आदमी पार्टी ही इस वादे को पूरा कर सकती है, क्योंकि पार्टी ने पहले भी कई मुफ्त योजनाओं के माध्यम से लोगों को लाभ पहुंचाया था। हालांकि आलोचक इन योजनाओं को केवल मुफ्तखोरी के रूप में देखते हैं, लेकिन इन योजनाओं ने वंचित और पिछड़े इलाकों की महिलाओं को वित्तीय और सामाजिक स्वतंत्रता दी, जैसा कि महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा योजना से स्पष्ट है। हालांकि, कुछ महिलाओं ने इन उपायों की आलोचना की और यह मांग की कि सरकार महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करे, जिससे उनकी स्थिति को सच्चे अर्थों मे सुधार जा सके।

युवाओं की बात करें तो उनकी प्रमुख चिंताएं रोजगार के अवसर, गुणवत्ता वाली शिक्षा और बुनियादी ढांचे के सुधार से जुड़ी थीं। उत्तर–पूर्व दिल्ली के युवा मतदाता बेहतर सड़कों, जल निकासी सुविधाओं और सफाई के लिए आवाज उठा रहे थे। युवाओं का एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर सक्रिय था, और विभिन्न राजनीतिक दलों ने सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं से जुड़ने का प्रयास किया। राजनीतिक नेताओं ने डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग करके युवा मतदाताओं से सीधे संवाद किया और उन्हें अपनी नीतियों के बारे में बताया। युवाओं के बीच जहां एक वर्ग वर्तमान सरकार के कार्यों से संतुष्ट था, वहीं दूसरा वर्ग बदलाव की तलाश में था।

अल्पसंख्यक समुदाय, विशेषकर मुसलमानों के लिए, यह चुनाव साम्प्रदायिक सद्भाव और अल्पसंख्यक कल्याण के मुद्दों से जुड़ा हुआ था। उत्तर–पूर्व दिल्ली के मुस्लिम मतदाता भाजपा की हिंदुत्ववादी राजनीति को लेकर संकोचशील थे और उन्होंने आम आदमी पार्टी को फिर से सत्ता में लाने का समर्थन किया। इन क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी ने अपनी सीटों को बनाए रखा, विशेष रूप से बाबरपुर और सीलमपुर में। कांग्रेस पार्टी का समर्थन लगभग न के बराबर था, लेकिन कुछ क्षेत्रों, जैसे कि सीलमपुर में स्लम इलाकों में, कांग्रेस ने अपना प्रभाव बनाए रखा। मुस्तफाबाद क्षेत्र में एआईएमआईएम द्वारा उम्मीदवार खड़ा करने की घटना भी इस चुनावी परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण रही, जो इस बात का संकेत था कि चुनाव में न केवल बड़ी पार्टियाँ, बल्कि छोटे दल भी प्रभावी हो रहे हैं।

इस चुनाव के परिणामों ने दिल्ली की राजनीति में महत्वपूर्ण बदलाव का संकेत दिया। भाजपा की 27 साल बाद सत्ता में वापसी ने एक नई राजनीतिक दिशा की ओर इशारा किया। इस बदलाव के पीछे कई कारण थे, विशेष रूप से आम आदमी पार्टी की घटती लोकप्रियता और 'केजरीवाल'

ब्रांड के प्रति असंतोष। दिल्ली में पिछले एक दशक तक शासन करने के बाद, आम आदमी पार्टी ने अपने शासन के दौरान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर सफलता नहीं हासिल की, जिसका परिणाम भाजपा की बढ़ती लोकप्रियता के रूप में सामने आया। कांग्रेस– जो अपने खोए हुए आधार को फिर से प्राप्त करने में नाकाम रही– ने भाजपा के लिए AAP के खिलाफ वोटों को एकजुट करने का अवसर प्रदान किया। इसके अतिरिक्त, भाजपा ने हिंदू वोटों को एकजुट करने और AAP तथा कांग्रेस के बीच वोटों के बंटवारे का फायदा उठाया।

भविष्य की राजनीति को देखते हुए सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि क्या भाजपा अपने वादों को पूरा करने में सक्षम होगी और क्या वह अपनी सत्ता को बनाए रखेगी, या क्या विपक्ष फिर से मजबूती से उभरकर भाजपा को चुनौती देगी? दिल्ली की राजनीतिक स्थिति बहुत ही गतिशील बनी हुई है और आगामी चुनावों में यह देखना दिलचस्प होगा कि राजनीतिक दल किस प्रकार से अपने कार्यों और नीतियों के माध्यम से मतदाताओं को प्रभावित करते हैं।

♦♦♦♦♦

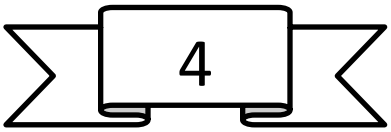

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025ः चुनाव और उसके प्रभाव

रहत रीत बराड़ और प्रांजल चौहान

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025, देश की राजधानी की राजनीति के इतिहास में एक मील का पत्थर है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने आम आदमी पार्टी (आप) को उखाड़ फेंका और आधे राज्य में 27 साल बाद सत्ता में वापसी की। भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर शानदार जीत हासिल की, जबकि आप के पास केवल 22 सीटें बची थीं। कांग्रेस, जो अतीत में राजधानी में एक प्रमुख राजनीतिक खिलाड़ी थी, कोई भी सीट सुरक्षित नहीं कर सकी, जो अपने पिछले अस्तित्व के स्पष्ट विपरीत है। कांग्रेस पार्टी अब पिछले 15 वर्षों से सत्ता से बाहर है, पिछली कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार 2014 से पहले शीला दीक्षित के नेतृत्व में गठित की गई थी।

2025 के चुनाव को मूल रूप से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच द्विध्रुवीय प्रतियोगिता के रूप में देखा जा सकता है। जबकि भाजपा 2015 के दिल्ली विधानसभा चुनावों से 40 सीटों की वृद्धि के साथ विजयी हुई, जबकि भाजपा के मतदाता शेयर में 7.3ः की छलांग है, जो इस चुनाव में कुल 45.8ः है। निवर्तमान सत्तारूढ़ पार्टी, ।।च् को वोट शेयर में 10ः की भारी गिरावट का सामना करना पड़ा, जिससे यह इस चुनाव में कुल मतदान का 43.8ः हो गया। जबकि प्रमुख प्रतिस्पर्धी दलों के बीच वोट शेयर का अंतर केवल 3ः है, लेकिन जब सीट शेयर में अनुवाद किया जाता है, तो आप ने इस बार भाजपा को 40 सीटें खो दी हैं। कभी दिल्ली की राजनीति में कभी हावी रही कांग्रेस ने सत्ता में अपने पिछले कार्यकाल के बाद से गिरावट का रुख बनाए रखा है।

अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप ने श्आम आदमीश के लिए कल्याणकारी योजनाओं पर जोर देकर शहर की राजनीति पर मजबूत पकड़ बनाई थी। लेकिन इस चुनाव में, भाजपा ने नई दिल्ली जैसे प्रमुख निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करके एक मजबूत वापसी की, जिसमें भाजपा के प्रवश साहिब सिंह (दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र) ने आप के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और आप के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 4,089 मतों से हराया। इसी तरह जंगपुरा में भाजपा

के तरविंदर सिंह मारवाह ने आप के मनीष सिसोदिया पर केवल 675 मतों से करीबी जीत हासिल की। आप के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन शकूर बस्ती में भाजपा के करनैल सिंह से हार गए, जिससे सत्तारूढ़ पार्टी को एक और हार का सामना करना पड़ा।

इस चुनाव में, सभी प्रमुख राजनीतिक दलों के शीर्ष स्टार प्रचारकों ने सक्रिय रूप से भाग लिया था। भाजपा के प्रचार अभियान का नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, असम के हेमंत बिस्वा सरमा और राजस्थान के भजन लाल शर्मा जैसे वरिष्ठ नेताओं ने किया। आम आदमी पार्टी के स्टार प्रचारकों में अरविंद केजरीवाल, निवर्तमान सीएम आतिशी, संजय सिंह, हरभजन सिंह और राघव चड्ढा थे। दिल्ली में पार्टियों द्वारा कई बड़ी रैलियां और अभियान चलाए गए, जिनमें से प्रत्येक ने बेहतर शासन, विकास और कल्याणकारी सब्सिडी के वादों के साथ मतदाताओं का ध्यान खींचने की कोशिश की।

आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में आक्रामक प्रचार अभियान चलाया। इन तीनों पार्टियों ने मतदाताओं को लुभाने के लिए चुनाव के बाद कल्याणकारी योजनाओं की श्रृंखला के वादे किए, या कोई भी मुफ्त में सौगात देने का वादा करता था. उनमें से प्रत्येक ने कुछ इकाइयों तक मुफ्त बिजली आपूर्ति, सब्सिडी वाले पानी के बिल, बेहतर शासन का वादा किया था। इसी तरह, महिला मतदाताओं को आकर्षित करने के लिए, इन सभी दलों ने वित्तीय सहायता का वादा किया, जिसमें AAP ने महिला सम्मान योजना के तहत प्रति माह ₹2100 का वादा किया, इस बीच, भाजपा और कांग्रेस ने ₹2500 प्रति माह का वादा किया। इस वित्तीय सहायता के वादे के बारे में दिल्ली के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में महिला मतदाताओं से बात करते हुए, उनमें से अधिकांश ने इस वादे को चुनावी हथकंडा के रूप में पाया और उल्लेख किया कि यह उनके मतदान निर्णय को प्रभावित नहीं करेगा। भाजपा ने मतदाताओं को यह भी आश्वासन दिया कि वे केजरीवाल सरकार द्वारा शुरू की गई कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखेंगे, जिसे आम आदमी पार्टी ने चेतावनी दी थी कि अगर भाजपा दिल्ली में सत्ता में आती है तो उसे बंद कर दिया जाएगा। मतदाताओं से अपील करने के लिए पार्टियों के बीच प्रतिस्पर्धा थी और प्रत्येक पार्टी ने एक–दूसरे के वादों से आगे निकलने की कोशिश की।

चुनाव अभियान के दौरान हम देखते हैं कि प्रत्येक पार्टी का शीर्ष नेतृत्व राज्य की समस्याओं के लिए दूसरे दल को दोषी ठहराता है। जबकि आम आदमी पार्टी दिल्ली के एलजी द्वारा अपने

सरकारी कार्यों में पैदा की गई निवारक के बारे में शिकायत करती रही। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने प्रदूषण और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाते हुए यमुना नदी के प्रदूषण से निपटने में अकुशल तरीके से काम करने के लिए आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा।

निवर्तमान आप सरकार, राज्य द्वारा संचालित अस्पतालों और स्कूलों में लाए गए सकारात्मक बदलावों और मध्यम और गरीब वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में शेखी बघारती है, जिसने उन्हें एक दशक से अधिक समय तक सत्ता में बने रहने में मदद की है। लेकिन इस बार यह नागरिक बुनियादी ढांचा और इसकी बिगड़ती स्थिति थी जो विधानसभा चुनावों में मतदाताओं का निर्णायक कारक बन गई। दिल्ली के निवासियों ने मुफ्त कल्याण योजना के लिए राज्य के विकास से समझौता करने पर केजरीवाल सरकार के प्रति अपना असंतोष खुले तौर पर व्यक्त किया है, जिसका लाभ केवल निम्न–मध्यम और गरीब वर्ग द्वारा उठाया जाता है।

आम आदमी पार्टी ने शुरू से ही स्पष्ट कर दिया था कि उसके मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार अरविंद केजरीवाल होंगे, जबकि भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर भरोसा करती रही और अपने मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार की घोषणा नहीं की। इसके बावजूद दिल्ली के मतदाता अपनी मतदान पसंद के बारे में स्पष्ट थे, क्योंकि निवर्तमान सरकार राज्य के नागरिक बुनियादी ढांचे के विकास में अक्षम साबित हुई, जिससे निवासियों के लिए रोजमर्रा की समस्या पैदा हो गई।

मुस्लिम मतदाताओं ने AAP का एक प्रमुख आधार बनाया, जिसके कारण अंततः 2015 और 2020 के चुनावों में AAP की जीत हुई। इस चुनाव में, हालांकि, मुस्लिम वोटों का विभाजन हुआ, वोटों को आप और कांग्रेस के बीच विभाजित किया गया। आप ने समुदाय के भीतर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ओखला, मटिया महल और बल्लीमारान सहित पांच निर्वाचन क्षेत्रों में मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था। दूसरी ओर, कांग्रेस ने सात सीटों पर मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा, जिसके परिणामस्वरूप मुस्लिम वोट का विभाजन हुआ। इस विभाजन ने भाजपा के पक्ष में काम किया, क्योंकि इसने एक पार्टी के पीछे मुस्लिम वोटों की एकाग्रता को कम कर दिया, जिससे अंततः कई क्षेत्रों में भाजपा को फायदा हुआ।

दिल्ली में आम आदमी पार्टी के पतन के पीछे के कारण

• कल्याणकारी योजनाएंः आम आदमी पार्टी ने कई कल्याणकारी योजनाओं को अपने घोषणापत्र का हिस्सा बनाया था, जिसे उन्होंने 2014 में सत्ता संभालने के बाद लागू किया था। आप ने मुफ्त बिजली (200 यूनिट तक), मुफ्त पानी और महिलाओं के लिए मुफ्त सवारी जैसी कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू कीं। हालांकि इन नीतियों ने आबादी के विशिष्ट वर्गों की मदद की, लेकिन वे अमीर और उच्च–मध्यम वर्गों के साथ अच्छी तरह से नहीं गए, जो इन्हें सार्वजनिक धन की बर्बादी के रूप में मानते थे। मतदाता राज्य में पेयजल आपूर्ति से असंतुष्ट थे, विशेष रूप से जेजे क्लस्टर और झुग्गियों में। अधिक मध्यम वर्ग की आबादी वाले अधिकृत इलाकों में, महत्वपूर्ण असंतोष अक्षम स्वच्छता प्रबंधन और सड़कों की खराब स्थिति थी। महत्वपूर्ण दीर्घकालिक विकास लाने में आप की अक्षमता के प्रति मतदाताओं के बीच इस तरह की नाराजगी, जिसने पार्टी के खिलाफ मोहभंग उत्पन्न किया।

• सत्ता विरोधीः खराब बुनियादी ढांचे के विकास, भ्रष्टाचार और अपर्याप्त नागरिक सुविधाओं जैसे कारणों से AAP के खिलाफ मजबूत सत्ता–विरोधी भावनाएं थीं। भाजपा ने विशेष रूप से शीश महल को निशाना बनाया, उच्च लागत पर निर्मित नए मुख्यमंत्री आवास, कथित तौर पर सार्वजनिक धन का उपयोग करके बनाया गया था और सरकारी भूमि की कीमत पर 10,000 वर्ग मीटर से 50,000 वर्ग मीटर तक बढ़ा दिया गया था, इसने अरविंद केजरीवाल की आम आदमी के रूप में धारणा को तोड़ दिया। भाजपा इस मुद्द और अन्य प्रचलित मुद्दों को सफलतापूर्वक भुनाने में सक्षम रही है, और दिल्ली के मतदाताओं के शासन विकल्प की पेशकश करने में सक्षम थी। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन जैसे वरिष्ठ आप नेताओं की गिरफ्तारी से पार्टी में विश्वास का क्षरण हुआ। जब भ्रष्टाचार को रोकन के लिए गठित पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भ्रष्टाचार के आरोपों के लिए निगरानी में होता है, तो ऐसा लगता है कि इस तरह के आरोपों का मतदाताओं के बीच AAP की विश्वसनीयता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है।

• बजट 2025 का प्रभावः चुनाव से चार दिन पहले 2025 के बजट की घोषणा का भी असर पड़ा। मध्यम वर्ग के लिए 12 लाख रुपये तक की कर छूट ने वास्तव में कई मध्यवर्गीय मतदाताओं को भाजपा में जीत लिया। दिल्ली के 40 से अधिक मतदाता मध्यम वर्ग के हैं, और इस तरह की कर राहत ने इस आर्थिक स्लैब से मतदाताओं का विश्वास जीतने में भाजपा को फायदा पहुंचाया, जैसा कि विधानसभा परिणाम में देखा जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) पर शासन किया, लेकिन यह किसी भी सराहनीय प्रगति को प्रदर्शित करने में

विफल रही, विशेष रूप से शहर के बुनियादी ढांचे को उन्नत करने की दिशा में, जिसने फिर से उनके समर्थन आधार को छीन लिया।

• कांग्रेस के साथ कोई गठजोड़ नहीं AAP और कांग्रेस के बीच गठजोड़ का अभाव एक और निर्णायक कारक था। कांग्रेस प्रमुख वोट बंटने वाली पार्टी है, इसने आप के वोट चुराए, खासकर महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्रों से। अगर आप और कांग्रेस ने गठबंधन किया होता, तो आप अधिक सीटें जीत सकती थी, और कांग्रेस दिल्ली में अपना खाता खोलने में सक्षम हो सकती थी। किसी के साथ गठबंधन न करने का यह विकल्प AAP और इंडिया ब्लॉक के लिए एक बहुत बड़ी भूल थी, जिसे 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था। कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिल रही है, यह दिल्ली में उसकी लगातार तीसरी हार है और 70 में से 67 कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई।

• वोट बैंक की गतिशीलताः समुदाय या धार्मिक तर्ज पर मतदान करना भारत की लंबाई और सांस में एक आम घटना है, दिल्ली का भी यही मामला है। 2015 और 2020 के विधानसभा चुनावों के दौरान आम आदमी पार्टी विशेष रूप से दलितों, झुग्गी बस्तियों के निवासियों और मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से सरकार बनाने में सफल रही थी। भ्रष्टाचार के आरोपों और दो बार सत्ता विरोधी लहर के साथ, AAP अपने मुस्लिम मतदाता को बनाए रखने में कामयाब रही, और 7 मुस्लिम बहुल सीटों (चांदनी चौक, बल्लीमारान, मताई महल, ओखला, बाबरपुर) में से 6 को बरकरार रखा, जबकि भाजपा ने मुस्तफाबाद की सीट जीती है। आप ने एससी आरक्षित सीटों में से 8 को भी बरकरार रखा, लेकिन इस बार बीजेपी ने बवाना, मादीपुर, मंगोलपुरी, त्रिलोकपुरी की 4 एससी आरक्षित सीटें जीतकर इन आरक्षित सीटों पर अपनी संख्या बढ़ा दी। भाजपा की समग्र जीत का श्रेय दिल्ली में मध्यम और उच्च वर्ग के समूहों के समर्थन को दिया जा सकता है।

निष्कर्ष

विधानसभा चुनाव के नतीजे बेहतर शासन की उम्मीद को दर्शाते हैं, जिसके लिए दिल्ली के मतदाताओं ने भाजपा को चुना है, दिल्ली के शासन के खंडित मॉडल में अधिक टिकाऊ और सुचारू शासन पाने की इच्छा के साथ। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने राजधानी में एक नए राजनोतिक युग का मार्ग प्रशस्त किया है। भाजपा की प्रचंड जीत ने न केवल राजनीतिक परिदृश्य बदला बल्कि लोकलुभावन कल्याणकारी नीतियों के बजाय विकास और सुशासन के प्रति लोगों के झुकाव को भी प्रतिबिंबित किया। आप की हार से संकेत मिलता है कि भाजपा से बढ़ती प्रतिस्पर्धा

के मद्देनजर अपनी नीतियों और रणनीतियों का फिर से विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हुए, भाजपा की चुनौती अपनी गति को बनाए रखने और अपने वादों पर खरा उतरने की होगी, जबकि आप को भविष्य के चुनावों में दिल्ली के मतदाताओं का विश्वास हासिल करन की उम्मीद करने के लिए अपने दृष्टिकोण को फिर से जांचना होगा।

♦♦♦♦♦

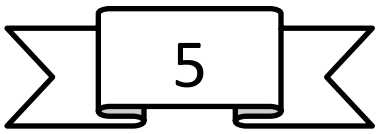

दिल्ली विधानसभा चुनाव रुझान (1990–2025): राजनीतिक परिवर्तन व परिवर्तित मतदान व्यवहार तथा मतदाता भावनाओं की अंतदृष्टि

प्रशांत कुमार

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सलोनी भाटी

विधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली, भारत की राजधानी, लंबे समय से एक राजनीतिक उपरिकेंद्र रहा है जहां इसके निवासियों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं अक्सर देश के व्यापक राजनीतिक प्रवचन को आकार देती हैं। शहर ने पिछले कुछ वर्षों में अपने राजनीतिक परिदृश्य में विभिन्न बदलावों को देखा है, जिसमें मतदाता बार–बार जवाबदेही, प्रगति और विकास की मांग कर रहे हैं। 1990 के दशक में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के शुरुआती प्रभुत्व से लेकर शीला दीक्षित क नेतृत्व में कांग्रेस के युग और आम आदमी पार्टी (आप) के जबरदस्त उदय तक, दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में भूकंपीय परिवर्तन देखे गए हैं। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों को एक और नाटकीय बदलाव के रूप में चिह्नित किया गया था, क्योंकि भाजपा ने आप शासन के वर्षों के बाद सफलतापूर्वक सत्ता हासिल की थी। यह लेख उन प्रमुख रुझानों की जांच करता है जिन्होंने पिछले 35 वर्षों में दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य को आकार दिया है, महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों और मतदाता भावनाओं को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर प्रकाश डाला है।

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन अधिनियम, 1991 और उसका प्रभाव

दिल्ली के शासन में एक ऐतिहासिक विकास राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (GNCTD) अधिनियम, 1991 था। इस अधिनियम ने दिल्ली को अपनी विधानसभा और एक मुख्यमंत्री रखने की अनुमति दी, जिससे यह अन्य भारतीय राज्यों के समान शासन प्रणाली के करीब आ गया। हालांकि, दी गई स्वायत्तता अधूरी थी, जिसमें पुलिस, कानून और व्यवस्था जैसे क्षेत्रों पर प्रमुख

शक्तियां थीं और भूमि केंद्र सरकार के पास शेष थी। समय के साथ, शक्तियों का यह विभाजन दिल्ली की निर्वाचित सरकार और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले उपराज्यपाल (एलजी) के बीच घर्षण का स्रोत बन गया। अधिनियम में वर्ष 2021 के संशोधन ने एलजी की शक्तियों को और मजबूत किया, दिल्ली के मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र को सीमित कर दिया, इस प्रकार शासन और संघवाद के भविष्य के बारे में बहस को हवा दी।

इन चुनौतियों के बावजूद, दिल्ली का राजनीतिक परिदृश्य जीवंत बना रहा, जिसमें मतदाता खेल में शक्ति गतिशीलता के बारे में अधिक जागरूक हो रहे थे। स्थानीय और केंद्रीय अधिकारियों के बीच चल रही इस रस्साकशी ने शहर में अधिकांश राजनीतिक प्रवचन को आकार दिया है, जिसमें राजनीतिक दल अक्सर एक–दूसरे पर पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए दिल्ली के शासन को कमजोर करने का आरोप लगाते हैं।

राजनीतिक व्यक्तित्व और दिल्ली के बदलते राजनीतिक परिदृश्य पर उनका प्रभाव

- मदन लाल खुरानाः भाजपा की प्रारंभिक सफलता के वास्तुकार (1993–1996)

मदन लाल खुराना को व्यापक रूप से 1991 के अधिनियम के लागू होने के बाद दिल्ली में भाजपा की शुरुआती सफलता की नींव रखने का श्रेय दिया जाता है। उनके नेतृत्व में, भाजपा ने 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में एक शानदार जीत हासिल की, जो एक प्रमुख राजनीतिक बदलाव को चिह्नित करता है। दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में खुराना का कार्यकाल शहर के बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के प्रयासों के लिए चिह्नित किया गया था, जिसमें सड़क विस्तार, विद्युतीकरण और बेहतर सार्वजनिक सुविधाओं सहित प्रमुख पहल शामिल थीं। उनके कार्यकाल ने सापक्ष राजनीतिक स्थिरता की अवधि को चिह्नित किया, और उनके नेतृत्व ने शहर में भाजपा के आधार को मजबूत करने में मदद की।

हालांकि, आंतरिक पार्टी संघर्ष और शासन के साथ बढ़ते असंतोष ने 1996 में उनके इस्तीफे का नेतृत्व किया, एक ऐसा कदम जिसने अन्य राजनीतिक ताकतों के उभरने का अवसर पैदा किया। इस अवधि ने दिल्ली की राजनीति की क्षणिक प्रकृति को उजागर किया, जहां मजबूत नेतृत्व भी दोर्घकालिक सफलता की गारंटी नहीं दे सकता था।

- शीला दीक्षितः सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली मुख्यमंत्री जिन्होंने दिल्ली को बदल दिया (1998–2013)

शीला दीक्षित निस्संदेह दिल्ली के इतिहास में सबसे प्रभावशाली राजनीतिक हस्तियों में से एक हैं। 1998 से 2013 तक 15 वर्षों तक दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते हुए, उनके नेतृत्व ने दिल्ली को एक आधुनिक महानगर में बदल दिया। उनके मार्गदर्शन में, शहर ने दिल्ली मेट्रो परियोजना सहित प्रमुख ढांचागत विकास देखा, जिसने सार्वजनिक परिवहन में क्रांति ला दी। उनकी सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और महिलाओं की सुरक्षा पर भी ध्यान केंद्रित किया, जिससे उन्हें शासन के लिए प्रशंसा मिली।

दीक्षित के प्रशासन ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जो एक महत्वपूर्ण आयोजन था जिसने भ्रष्टाचार से संबंधित विवादों के बावजूद दिल्ली के वैश्विक कद को बढ़ाया। हालांकि, उनका नेतृत्व 2013 में समाप्त हो गया, जब बढ़ती सत्ता–विरोधी भावनाओं और भ्रष्टाचार के आरोपों, विशेष रूप से राष्ट्रमंडल खेलों के संबंध में, उनकी पार्टी की हार का कारण बनी। इस अवधि के दौरान दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में आप के प्रवेश ने कांग्रेस के लिए और चुनौतियां जोड़ दीं, एक नए राजनीतिक यग के लिए मंच तैयार किया।

- अरविंद केजरीवालः आप लहर और भ्रष्टाचार विरोधी राजनीति (2013–2025)

आम आदमी पार्टी (आप) का चेहरा अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में राजनीतिक गतिशीलता बदल दी। 2011 में जन लोकपाल आंदोलन के साथ शुरू हुए उनके भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन ने आप के गठन के लिए आधार तैयार किया। 2013 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में उनकी शुरुआतो राजनीतिक शुरुआत ने कई लोगों को चौंका दिया, क्योंकि आप ने 70 में से 28 सीटें जीतीं, जिससे यह राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी बन गया।

केजरीवाल के पहले कार्यकाल में मुफ्त पानी, सब्सिडी वाली बिजली और मोहल्ला क्लीनिक जैसी लोकलुभावन योजनाओं के रूप में चिह्नित किया गया था, जिसने उन्हें निम्न और मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच बड़े पैमाने पर समर्थन प्राप्त किया। हालांकि, अपने महत्वपूर्ण कानून को पारित करने में असमर्थता के बाद कार्यालय में केवल 49 दिनों के बाद उनके इस्तीफे ने उनके नेतृत्व और शासन क्षमताओं के बारे में सवाल उठाए।

इसके बावजूद, केजरीवाल की पार्टी ने 2015 में भारी वापसी की, 70 में से 67 सीटें जीतीं, और बाद के 2020 के चुनावों में राज्य की राजनीति पर हावी रही। हालांकि, भ्रष्टाचार के आरोपों और शराब नीति घोटाले के कारण 2023–2025 में उनकी प्रतिष्ठा को महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जिसने उनकी भ्रष्टाचार–विरोधी साख को खत्म कर दिया।

- मनीष सिसोदियाः दिल्ली के शिक्षा सुधारों के वास्तुकार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राज्य की शिक्षा प्रणाली को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके सुधारों ने बुनियादी ढांचे, शिक्षक प्रशिक्षण और स्कूल पाठ्यक्रम में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया। उनके नेतृत्व में, दिल्ली के सरकारी स्कूलों ने अपनी शिक्षा की गुणवत्ता के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त की। सिसोदिया के काम ने उन्हें घरेलू और वैश्विक स्तर पर, विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के शिक्षा सुधार के क्षेत्र में प्रशंसा अर्जित की।

हालांकि, 2023 में शराब नीति घोटाले के संबंध में उनकी गिरफ्तारी ने उनकी छवि को धूमिल किया और AAP की विश्वसनीयता को काफी नुकसान पहुंचाया। सिसोदिया का पतन आप के भीतर आंतरिक विरोधाभासों का प्रतीक बन गया, जिससे 2025 के चुनावों में पार्टी का पतन हो गया

- राष्टोय नेताओं की भूमिकाः नरेंद्र मोदी और अमित शाह

हाल के वर्षों में भाजपा की दिल्ली की रणनीति को राष्ट्रीय नेताओं, विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा काफी आकार दिया गया है। उनका प्रभाव 2014 के बाद अधिक स्पष्ट हो गया, जब भाजपा का राष्ट्रीय कद बढ़ गया। मोदी और शाह ने दिल्ली में रणनीतिक रूप से भ्रष्टाचार विरोधी कार्ड खेला, जिसमें आप के शासन में विसंगतियों पर जोर दिया गया, विशेष रूप से शराब नीति घोटाले और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोपों पर ध्यान केंद्रित किया गया।

इसके अतिरिक्त, कभी आप के प्रति वफादार रहे मध्यम वर्ग के मतदाताओं पर उनके ध्यान ने 2025 में भाजपा की वापसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. भाजपा के आक्रामक प्रचार, जिसमें महिलाओं और बुजुर्गों के लिए वित्तीय सहायता जैसी लोकलुभावन योजनाओं को शामिल किया गया था, निरंतर बुनियादी ढांचे के विकास के वादों के साथ, दिल्ली के मतदाताओं के साथ गूंज गया, उनकी जीत सुनिश्चित हुई।

1991 के जीएनसीटीडी अधिनियम के पारित होने से पहले, दिल्ली को सीधे केंद्र सरकार द्वारा प्रशासित किया जाता था। हालाँकि, नए अधिनियम ने एक विधान सभा की स्थापना और शासन के अधिक लोकतांत्रिक रूप का मार्ग प्रशस्त किया। 1993 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में, भाजपा

प्रमुख शक्ति के रूप में उभरी, जिसने 70 में से 49 सीटें हासिल कीं और दिल्ली में पहली राज्य स्तरीय सरकार बनाई। इस जीत ने शहर में भाजपा की प्रमुखता को चिह्नित किया।

एक केस स्टडीः पूर्वी दिल्ली का परिवर्तन (1993–1998)

1990 के दशक के मध्य में, पूर्वी दिल्ली भाजपा के लिए एक प्रमुख गढ़ बन गया, जिसमें बुनियादी ढांचे के विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया था। खुराना के नेतृत्व में, सड़क नेटवर्क, बिजली और पानी की आपूर्ति में सुधार के लिए महत्वपूर्ण निवेश किए गए थे। हालांकि, स्वच्छता और पानी की कमी के मुद्दों ने असंतोष को बढ़ा दिया, खासकर पूर्वी दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में। 1998 के चुनावों तक, इस क्षेत्र में भाजपा की लोकप्रियता कम होने लगी, जिससे कांग्रेस के पुनरुत्थान का मार्ग प्रशस्त हुआ।

2025ः बीजेपी की बड़ी वापसी

2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों ने राजनीतिक परिदृश्य में एक बड़ा बदलाव किया। भाजपा ने 48 सीटें हासिल कीं, आप 22 सीटों पर सिमट गई और कांग्रेस महत्वपूर्ण प्रभाव डालने में विफल रही। 2025 में आप के पतन में प्रमुख योगदानकर्ताओं में से एक शराब नीति घोटाला था, जहां आप के वरिष्ठ नेताओं पर रिश्वत के बदले निजी विक्रेताओं का पक्ष लेने का आरोप लगाया गया था। इस घोटाले ने आम आदमी पार्टी की विश्वसनीयता को बुरी तरह प्रभावित किया, खासकर मध्यम वर्ग के मतदाताओं के बीच, जिन्होंने पहले केजरीवाल के भ्रष्टाचार विरोधी एजेंडे का समर्थन किया था।

क्या हुआ बीजेपी की जीत?

1. आम आदमी पार्टी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपः शराब नीति घोटाले और वित्तीय कुप्रबंधन के आरोपों ने आम आदमी पार्टी की छवि को गंभीर नुकसान पहुंचाया।

2. भाजपा का कल्याण–उन्मुख अभियानः अटल कैंटीन के माध्यम से महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों के लिए वित्तीय सहायता और किफायती भोजन जैसी योजनाओं पर भाजपा का ध्यान केंद्रित करने से समर्थन मिला।

3. मध्यवर्गीय मतदाताओं में बदलावः कई मध्यवर्गीय मतदाता, जो कभी आप के प्रति वफादार थे, आंतरिक संघर्षों और भ्रष्टाचार के घोटालों के कारण भाजपा में चले गए।

4. आप का नेतृत्व संकटः अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे प्रमुख नेताओं की हार, दोनों अपनी सीटें हार गए, ने AAP के राजनीतिक आधार के कमजोर होने को रेखांकित किया.

समाप्ति

2025 के चुनाव दिल्ली में एक महत्वपूर्ण राजनीतिक बदलाव का संकेत देते हैं। जैसा कि एक प्रमुख राजनीतिक सिद्धांतकार सुहास पलशिकर का तर्क है, दिल्ली में भाजपा की जीत शहरी वोटों को मजबूत करने की एक बड़ी राष्ट्रीय रणनीति का हिस्सा है। हालांकि, दिल्ली के मतदाताओं को हमेशा पार्टी वफादारी पर शासन और परिणामों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाता है। राजधानी के चुनाव में देखी गई सभी चिंताओं और चुनौतियों के बावजूद, कुछ सवाल अभी भी खामियों में बने हुए हैं। उन्हें इस प्रकार उठाया जा सकता हैय क्या बीजेपी अपनी गति को बनाए रख पाएगी, या आने वाले वर्षों में आप वापसी करेगी? क्या दिल्ली में कांग्रेस के फिर से पैर जमाने की संभावना है, खासकर हाल के वर्षों में अपने निराशाजनक प्रदर्शन के बाद? क्या एक नई राजनीतिक ताकत उभरेगी, जैसा कि आप ने एक दशक पहले किया था, दिल्ली के राजनीतिक परिदृश्य में नए दृष्टिकोण और चुनौतियां ला रही है? एक बात जो निश्चित है, वह है दिल्ली के मतदाताओं का राजनीतिक व्यवहार, कि वे अपने नेताओं को जवाबदेह ठहराना जारी रखेंगे, और राजनीतिक भाग्य शहर के क्षितिज के रूप में तेजी से बदल जाएगा।

♦♦♦♦♦

6

दिल्ली विधानसभा 2025 : चुनाव एवं प्रभाव

सजल जैन

स्नातक विद्यार्थी, आगरा कॉलेज

प्रस्तावना

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन का प्रतीक नहीं था, बल्कि इसके परिणामों ने यह दर्शाया कि भारत की राजधानी में मतदाता अब किस दिशा में राजनीतिक झुकाव रखते हैं। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 27 वर्षों के बाद दिल्ली की सत्ता में वापसी की, जिसने आम आदमी पार्टी (आप) के एक दशक लंबे शासन को समाप्त कर दिया। इस चुनाव ने न केवल दिल्ली की राजनीति में नई दिशा निर्धारित की बल्कि भारत में राष्ट्रवादी विचारधारा की स्वीकृति और उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता को भी उजागर किया।

इस शोध लेख में दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के राजनीतिक और राष्ट्रवादी पहलुओं का गहन विश्लेषण किया जाएगा। इसके अंतर्गत चुनाव परिणामों के कारण, विभिन्न राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ, मतदाताओं के व्यवहार में आए बदलाव, राष्ट्रवाद की भूमिका, और इन चुनावों का राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव शामिल किया जाएगा। यह अध्ययन तटस्थ दृष्टिकोण से किया जाएगा, जिससे यह समझने में सहायता मिलेगी कि भारतीय लोकतंत्र किस दिशा में अग्रसर हो रहा है।

दिल्ली चुनाव 2025: परिणाम और राजनीतिक परिदृश्य

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी ने 48 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया, जबकि आम आदमी पार्टी को 22 सीटों पर संतोष करना पड़ा। वहीं, कांग्रेस लगातार तीसरी बार शून्य पर रही। यह चुनाव कई दृष्टियों से विशिष्ट रहा, क्योंकि यह एक दशक तक चले आम आदमी पार्टी के शासन का अंत साबित हुआ और दिल्ली की राजनीति में नए समीकरण बने।

इस चुनाव में भाजपा की सफलता का प्रमुख कारण उसकी राष्ट्रवादी और विकास आधारित नीतियाँ रहीं। केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों ने भाजपा के पक्ष में माहौल बनाया। दूसरी ओर, आम आदमी पार्टी की पराजय का कारण उसकी सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप, प्रशासनिक विफलताएँ, और आपराधिक मामलों में फँसे उसके नेताओं की छवि रही।

राजनीतिक दृष्टि से यह चुनाव भारतीय लोकतंत्र में एक बड़े बदलाव का संकेत देता है। यह इंगित करता है कि दिल्ली के मतदाता अब केवल मुफ्त सुविधाओं के वादों पर भरोसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे दीर्घकालिक विकास और सुशासन को प्राथमिकता दे रहे हैं।

राजनीतिक दलों की रणनीतियाँ और उनकी प्रभावशीलता

1- भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)

भाजपा ने दिल्ली में बुनियादी ढाँचे के विकास को प्राथमिकता देते हुए परिवहन, जल आपूर्ति, स्वच्छता, और डिजिटल कनेक्टिविटी को मजबूत करने का संकल्प लिया। पार्टी ने राजधानी को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए मेट्रो विस्तार, नई एक्सप्रेसवे परियोजनाओं, और स्वच्छ यमुना अभियान पर जोर दिया। दिल्ली की जल संकट समस्या को हल करने के लिए रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, वाटर रीसाइक्लिंग प्लांट्स, और पाइपलाइन सुधार को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया गया। इसके अलावा, भाजपा ने दिल्ली के औद्योगिक क्षेत्रों को डिजिटल रूप से सक्षम बनाने और स्टार्टअप एवं ई–कॉमर्स हब के रूप में विकसित करने का वादा किया, जिससे युवा उद्यमियों के लिए नए अवसर सृजित हों।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को बढ़ावा देते हुए भाजपा ने दिल्ली की ऐतिहासिक और धार्मिक धरोहर को पुनर्जीवित करने की योजना बनाई। प्राचीन मंदिरों के पुनर्निर्माण, सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण, और भारतीय परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए विशेष घोषणाएँ की गइं। पार्टी ने योग, आयुर्वेद, और संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नई संस्थाएँ खोलने और वैदिक अध्ययन केंद्र स्थापित करने का संकल्प लिया। इसके साथ ही, भाजपा ने दिल्ली को राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद–विरोधी रणनीतियों के केंद्र के रूप में विकसित करने का भी वादा किया, जिससे देश की राजधानी को सुरक्षित और आधुनिक बनाने की दिशा में कार्य किया जा सके।

2- आम आदमी पार्टी (आप)

आम आदमी पार्टी (आप) ने अपने पिछले कार्यकालों में शिक्षा, स्वास्थ्य, और जल आपूर्ति जैसे बुनियादी सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया था, जिससे उसे पहले व्यापक जनसमर्थन मिला था। हालांकि, 2025 के चुनाव में पार्टी की सबसे बड़ी चुनौती उसकी प्रशासनिक कमजोरियाँ, भ्रष्टाचार के आरोप, और नेतृत्व संकट रहा। दिल्ली सरकार में घोटालों की बढ़ती घटनाओं और कई नेताओं पर लगे कानूनी मामलों ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुँचाया। इसके अलावा, राष्ट्रवाद विरोधी रुख और केंद्र सरकार के साथ लगातार टकराव की राजनीति ने मतदाताओं को दूर कर दिया, जिससे पार्टी के समर्थन में भारी गिरावट देखी गई।

3- भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इस चुनाव में पूरी तरह अप्रासंगिक साबित हुई, क्योंकि पार्टी की न तो कोई स्पष्ट रणनीति थी और न ही मजबूत नेतृत्व। कांग्रेस का संगठनात्मक ढाँचा कमजोर पड़ चुका था, और जनता के बीच विश्वास बहाल करने में पार्टी विफल रही। स्थानीय नेतृत्व का अभाव, शीर्ष नेताओं की निष्क्रियता, और जमीनी स्तर पर जनसंपर्क की कमी ने कांग्रेस को चुनावी दौड़ से लगभग बाहर कर दिया। जहाँ भाजपा ने राष्ट्रवाद और विकास का एजेंडा आगे बढ़ाया और आप ने अपनी पुरानी नीतियों पर भरोसा किया, वहीं कांग्रेस कोई ठोस मुद्दा नहीं उठा सकी, जिससे वह दिल्ली की राजनीति में हाशिये पर चली गई।

मतदाताओं का व्यवहार और समाज में परिवर्तन

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं के व्यवहार में महत्वपूर्ण परिवर्तन देखा गया। पिछले चुनावों में मुफ्त बिजली, पानी, और शिक्षा जैसे लोकलुभावन वादों का बोलबाला था, लेकिन इस बार विकास, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, और राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुख चुनावी मुद्दे बने। भाजपा ने अपने राष्ट्रवादो एजेंडे और बुनियादी ढाँचे के विकास पर जोर दिया, जिससे मतदाताओं का झुकाव उसकी ओर बढ़ा। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 68% मतदाताओं ने विकास और सुशासन को प्राथमिकता दी, जबकि केवल 32% ने मुफ्त योजनाओं को अपना प्रमुख मुद्दा बताया। इस बदलाव ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली के मतदाता अब दीर्घकालिक विकास और स्थिर शासन को अधिक महत्व देने लगे हैं।

1-युवा और प्रथम बार के मतदाता

युवा और प्रथम बार के मतदाताओं ने इस चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाई। दिल्ली में 18–25 आयु वर्ग के लगभग 12 लाख नए मतदाता जुड़े, जिनमें से एक बड़ा हिस्सा आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया, और स्टार्टअप संस्कृति से प्रभावित था। भाजपा ने युवा रोजगार, स्टार्टअप्स को बढ़ावा, और डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपने अभियान का मुख्य हिस्सा बनाया, जिससे वह युवा वोटर्स के बीच लोकप्रिय रही। पोस्ट पोल एनालिसिस के अनुसार, 18–30 वर्ष के 57% मतदाताओं ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया, जबकि आप और कांग्रेस इस वर्ग में अपनी पकड़ बनाने में विफल रहीं।

2-महिलाओं और मध्यम वर्ग का समर्थन

महिला और मध्यम वर्ग के मतदाताओं ने भी भाजपा की जीत में अहम योगदान दिया। भाजपा की महिला सुरक्षा नीतियाँ, जैसे दिल्ली में CCTV कैमरों की संख्या बढ़ाना, फास्ट–ट्रैक अदालतों का विस्तार, और महिला हेल्पलाइन को सशक्त बनाना, महिलाओं को आकर्षित करने में सफल रहीं। इसके अलावा, मध्यम वर्ग के लिए आयकर छूट, स्वास्थ्य बीमा, और छोटे व्यवसायों के लिए आसान लोन योजनाएँ भाजपा के पक्ष में रहीं। चुनावी विश्लेषण के अनुसार, महिला मतदाताओं में भाजपा को 54% समर्थन मिला, जबकि आप को 38% और कांग्रेस को मात्र 8% वोट मिले।

3-धार्मिक और जातीय समीकरण

2025 के चुनाव में जातिगत राजनीति की तुलना में धार्मिक ध्रुवीकरण अधिक प्रभावी रहा। दिल्ली में परंपरागत रूप से जातिगत समीकरण चुनावों को प्रभावित करते थे, लेकिन इस बार भाजपा के राष्ट्रवादी एजेंडे ने इसे पीछे छोड़ दिया। हिंदू मतदाताओं का 65% से अधिक समर्थन भाजपा को मिला, जबकि आप और कांग्रेस अल्पसंख्यक वोट बैंक को एकजुट करने में असफल रहीं। भाजपा ने राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को अपने अभियान का हिस्सा बनाकर बहुसंख्यक समुदाय का विश्वास जीता। वहीं, कांग्रेस और आप की अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति उनके लिए उलटी साबित हुई, जिससे भाजपा को स्पष्ट बढ़त मिली।

राष्ट्रीय राजनीति पर प्रभाव

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजे भारतीय राजनीति में एक नए दौर की शुरुआत का संकेत देते हैं, जहाँ राष्ट्रवाद, विकास, और सुशासन मतदाताओं के लिए प्रमुख चुनावी मुद्दे बन चुके हैं।

इस चुनाव का प्रभाव केवल दिल्ली तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर भी दिखेगा। भाजपा की जीत ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश की राजनीति अब केवल लोकलुभावन वादों पर केंद्रित नहीं है, बल्कि मतदाता राष्ट्रवाद और विकास–आधारित राजनीति को अधिक महत्व देने लगे हैं।

भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त

दिल्ली में जीत भाजपा के लिए मनोवैज्ञानिक बढ़त के रूप में कार्य करेगी, जिससे उसे आगामी 2029 के लोकसभा चुनावों में अतिरिक्त आत्मविश्वास मिलेगा। इस चुनाव में भाजपा ने राष्ट्रवाद, सुशासन और विकास के मॉडल को आगे बढ़ाया, जो मतदाताओं के बीच स्वीकार्य साबित हुआ। एक सर्वेक्षण के अनुसार, 72% भाजपा समर्थकों ने माना कि यह जीत पार्टी की राष्ट्रवादी नीतियों की स्वीकार्यता को दर्शाती है। भाजपा नेतृत्व इस जीत को "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास" नीति की सफलता के रूप में देखेगा और इसे राष्ट्रीय स्तर पर दोहराने की कोशिश करेगा।

विपक्षी दलों की रणनीतिक पुनर्रचना

आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को इस चुनाव के नतीजों से सबक लेते हुए अपनी रणनीतियों पर पुनर्विचार करना होगा। यदि वे अगले चुनावों में प्रभावी रहना चाहते हैं, तो उन्हें न केवल भ्रष्टाचार के आरोपों और प्रशासनिक कमजोरियों से उबरना होगा, बल्कि अपनी विचारधारा को भी स्पष्ट करना होगा। 2024 के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस का वोट शेयर 19-5% था, लेकिन ताजा अनुमानों के अनुसार, यह 2029 में घटकर 14% तक आ सकता है। इसी तरह, आम आदमी पार्टी के लिए भी स्थिति गंभीर हो सकती है, क्योंकि उसकी राजनीति अब मतदाताओं को उतनी आकर्षक नहीं लग रही है। विपक्षी दलों को अब स्थायी और ठोस नीतियों के साथ सामने आना होगा, अन्यथा वे और भी हाशिए पर जा सकते हैं।

राष्ट्रवाद की राजनीतिक स्वीकार्यता

इस चुनाव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रवाद अब केवल एक वैचारिक बहस का विषय नहीं रहा, बल्कि यह भारतीय राजनीति की मुख्यधारा का अभिन्न अंग बन चुका है। एक चुनावी विश्लेषण के अनुसार, 68% मतदाताओं ने राष्ट्रवाद को एक निर्णायक चुनावी मुद्दा माना, जो 2019 के लोकसभा चुनावों में मात्र 52% था। भाजपा ने इसे बखूबी भुनाया और अपने राष्ट्रवादी एजेंडे को

मजबूती से प्रस्तुत किया। इस प्रवृत्ति को देखते हुए, भविष्य में अन्य राजनीतिक दलों को भी राष्ट्रवाद को अपनी राजनीति में शामिल करना होगा, क्योंकि यह भारतीय मतदाताओं की प्राथमिकता बन चुका है। यदि विपक्षी दल इस मुद्दे को नजरअंदाज करते हैं, तो वे खुद को लगातार कमजोर स्थिति में पाएंगे।

निष्कर्ष

दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 ने भारत में राष्ट्रवादी राजनीति की बढ़ती स्वीकृति को स्पष्ट कर दिया है। चुनावी सर्वेक्षणों के अनुसार, 68% मतदाताओं ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सांस्कृतिक पहचान को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बताया, जबकि 2020 में यह आंकड़ा केवल 52% था। भाजपा ने इस चुनाव में बुनियादी ढांचे के विकास, डिजिटल अर्थव्यवस्था, महिला सुरक्षा, और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन पर विशेष ध्यान दिया, जिससे उसे 46% वोट शेयर प्राप्त हुआ, जो 2020 के चुनावों की तुलना में 8% की वृद्धि को दर्शाता है। आम आदमी पार्टी (आप) और कांग्रेस ने अपनी पारंपरिक मुफ्त योजनाओं और लोकलुभावन नीतियों पर जोर दिया, लेकिन 55% मतदाताओं ने इन्हें अल्पकालिक समाधान करार दिया, जिससे विपक्ष की स्थिति कमजोर होती गई।

इस चुनाव का व्यापक प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर भी पड़ेगा, क्योंकि यह दर्शाता है कि भारतीय राजनीति अब राष्ट्रवाद और विकास की ओर अधिक झुक रही है। भाजपा की यह जीत उसे 2029 के लोकसभा चुनावों में मजबूत आधार प्रदान करेगी, जबकि विपक्षी दलों को अपनी रणनीतियों को पुनर्गठित करने की आवश्यकता होगी। आंकड़ों के अनुसार, कांग्रेस का वोट शेयर 2024 के लोकसभा चुनाव में 19-5% था, जो अब घटकर 14% तक आ सकता है, जबकि आप की स्थिति और भी कमजोर हो सकती है। वहीं, 72% भाजपा समर्थकों ने माना कि यह जीत राष्ट्रवादी एजेंडे की स्वीकृति को दर्शाती है। यदि यह प्रवृत्ति जारी रहती है, तो भारत की राजनीति आने वाले वर्षों में और अधिक राष्ट्रवादी, विकासोन्मुखी और सुशासन केंद्रित होती जाएगी।

सन्दर्भ सूची

- भारतीय चुनाव आयोग (2025)। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025: मतदाता भागीदारी और दलों का प्रदर्शन। प्राप्त किया गया https://eci-gov-पद से।
- सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज (CSDS)। (2025)। दिल्ली में बदलती चुनावी प्राथमिकताएँरू एक पश्चात सर्वेक्षण विश्लेषण। नई दिल्लीः CSDS प्रकाशन।
- इंडियन एक्सप्रेस। (2025] फरवरी 26)। दिल्ली चुनाव 2025: भाजपा की जीत और इसके राष्ट्रीय प्रभाव। प्राप्त किया गया https://indianeÛpress-com से।
- शर्मा, आर। (2025)। भारतीय राजनीति में राष्ट्रवाद का उदयः दिल्ली चुनाव का एक अध्ययन। जर्नल ऑफ पॉलिटिकल स्टडीज, 12(1), 45–67।

♦♦♦♦♦

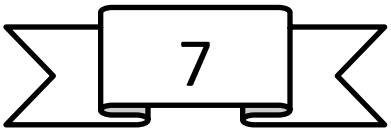

जलवायु परिवर्तन, निर्धनता व मुफ्त सुविधाएंः दिल्ली चुनाव के विषय

प्रार्थना श्रीवास्तव

परास्नातक छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

सिद्धार्थ

परास्नातक छात्र, राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

इस बार दिल्ली चुनाव काफी दिलचस्प रहे। इस चुनाव ने लोकतंत्र की खूबसूरती को बेहतरीन ढंग से दर्शाया। तीन बार से लगातार आम आदमी पार्टी के जीतने के बाद २७ साल बाद भाजपा की सरकार बनी। यह दर्शाता है कि लोकतंत्र जनता के लिए और जनता से ही है।

जहां एक तरफ यह चुनाव लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ हम लोकतंत्र के सुचारू रूप से चलने के लिए चुनौतियां भी देखते हैं। यह चुनाव कई मुद्दों पर लड़ा गया, जो हर चुनाव में आम होते हैं, जैसे विकास, रोजगार और कानून व्यवस्था। किन्तु, हम अपन लेख के माध्यम से उन अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं, जो चर्चा में होने के बावजूद लोगों के मन तक नहीं पहुंचे और जिन्हें मुख्यधारा में जगह नहीं मिली। इस लेख के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे कि किन कारणों से जलवायु परिवर्तन, गरीबी और मुफ्त सुविधाओं जैसे विषयों को कम प्राथमिकता मिली। हालांकि, मुफ्त सुविधाओं का विषय बहुचर्चित रहा, किन्तु इसका जनता पर सही मायनों में क्या असर होता है, इसे समझने का प्रयास हमने इस लेख में किया है।

जलवायु परिवर्तन और दिल्ली चुनाव

विकास के नाम पर आज हम प्रकृति के विनाश के उस स्तर पर पहुंच गए हैं, जहां से वापस आने का रास्ता हमने खो दिया है। आज दिल्ली सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में से एक है। इसका मुख्य कारण हमारी विकास की गलत अवधारणा है। हमारी शिक्षा ही ऐसी हुई है कि विकास का अर्थ हमारे लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन और भोग करना है। हम देखते हैं कि लोग पेड़ लगाने

या इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देकर निश्चिंत हो जाते हैं कि उन्होंने पर्यावरण को बचाने में अपना कर्तव्य निभा दिया, किन्तु यह स्वयं को धोखा देना हुआ।

यह बिल्कुल भी गलत नहीं है कि पेड़ हमें बचाएंगे और इलेक्ट्रिक वाहन, पेट्रोलध्डीजल जैसे वाहनों से बेहतर हैं, किन्तु यह मूल समाधान नहीं है। मुख्य समाधान यह है कि हमें अपने विकास और प्राकृतिक संसाधनों के प्रति जो समझ है, उसे बदलना होगा। यह अवधारणा कि विकास केवल जीडीपी के बढ़ने से होता है, गलत है। बिना प्रकृति के दोहन के भी आर्थिक विकास संभव है। हमें विकास की इस परिभाषा को बदलना होगा। आज हमें लगता है कि संसाधनों के भोग में ही असली खुशी होती है, लेकिन हमें खुशी और आनंद के बीच का अंतर समझना होगा।

भोग की अवधारणा को समाप्त करके ही हम जलवायु परिवर्तन जैसे खतरे से बच सकते हैं। दुख की बात यह है कि पर्यावरण परिवर्तन जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के घोषणा पत्र में भी नहीं दिखते। अखबारों में आर्थिक विकास की खबरें तो मिल जाएंगी, लेकिन पर्यावरण परिवतन की एक छोटी सी लाइन पन्ने के कोने में लिखी रहती है। सोशल मीडिया में तुच्छ विषय रातों–रात वायरल हो जाते हैं, किन्तु पर्यावरण जैसे मुख्य विषय मुख्यधारा में आने के लिए संघर्षरत रहते हैं।

गरीबी, चुनावी राजनीति और मुफ्त सुविधाएं

तथाकथित मुफ्त सुविधाओं की राजनीति की उत्पत्ति कल्याणकारी राज्य से हुई है जो 1930 के दशक के बाद समाज में संसाधनों के पुनर्वितरण के एक तरीके के रूप में उभरा। लोगों ने यह कहते हुए मुफ्त सुविधाओं (फ्रीबीज) और कल्याण (वेलफेयर) के बीच अंतर किया है कि मुफ्त उपहार विशेष रूप से मतदाताओं को लुभाने के लिए विशेष वर्गों के लिए अल्पकालिक, चुनाव पूर्व घोषणाएं हैं, जबकि कल्याण सामाजिक न्याय के नजरिए से समाज में दीर्घकालिक हस्तक्षेप है। मुफ्त चीजों का मुद्दा नया नहीं है, 1990 क दशक से भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जैसे कि दक्षिण भारतीय राज्यों में सिलाई मशीनों या प्रेशर कुकर के वितरण की योजनाएँ। हालाँकि हाल के दिनों में यह मुद्दा राष्ट्रीय बहसों में अधिक प्रमुख हो गया है। दिल्ली चुनाव में मुफ्त सुविधाओं के वादे हावी रहे। यहां तक कि आम आदमी पार्टी की इन योजनाओं का विरोध करने वाली बीजेपी भी उसी रास्ते पर चल पड़ी है। सभी तीन प्रमुख दलों ने अपना अभियान मुफ्त चीजों पर केन्द्रित रखा (घोषणापत्र का हवाला देते हुए), हम यह कह सकते हैं कि यह चुनाव मुफ्त सुविधाओं की राजनीति का खंडन नहीं था, बल्कि उन्हें पुनः वैधता प्रदान करना था ।

हमारे सीजीएस (वैश्विक राजनीतिक केंद्र) के सर्वे के दौरान, जब हमने दिल्ली के आदर्श नगर और मॉडल टाऊन के लालबाग क्षेत्र की जुग्गी–झोपड़ियों की स्थिति देखी, तब हमें फ्रीबीज के मुद्दे को करीब से समझने का अवसर मिला जिसने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि गरीबी कोई प्राकृतिक अवस्था नहीं है। बल्कि यह समाज के लालच और अनियंत्रित भोग का परिणाम है। कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से गरीब नहीं होता, बल्कि वह एक ऐसे सामाजिक ढांचे में जी रहा होता है, जिसकी नींव ही गलत अवधारणा पर बनी हुई है।

गरीबी केवल मनुष्यों में ही दिखती है, जानवरों या पेड़–पौधों में नहीं। क्योंकि वे उतना ही उपभोग करते हैं, जितनी उन्हें जरूरत होती है। किन्तु, हम इंसान अपनी जरूरतों से अधिक इकट्ठा कर लेते हैं, जिससे आय का असमान वितरण जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।

हमारे सर्वे से यह पता चला कि जुग्गी–झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को पर्यावरण, प्रदूषण, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों से अधिक फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए सबसे अच्छा नेता वही होता है, जो उन्हें जितना अधिक मुफ्त सुविधाएं दे सके। उनकी आर्थिक स्थिति उन्हें रोटी, कपड़ा और मकान के बाहर सोचने ही नहीं देती। इसलिए, उनके वोट का आधार मुद्दे नहीं, बल्कि मुफ्त सुविधाएं कौन अच्छी दे रहा है, इस पर निर्भर करता है।

हम जानते हैं कि यदि इसी आधार पर हम अपने नेता चुनते रहे, तो असली विकास कभी नहीं होगा। लोगों में बेहतर शिक्षा और जागरूकता पैदा करनी होगी, जिससे वे यह समझ सकें कि उनकी स्थिति बदल सकती है यदि वे सवाल करना शुरू करें। गरीबी में रहना किसी की नियति नहीं ह। हमें यह समझ विकसित करनी होगी कि केवल रोटी, कपड़ा और मकान पाना ही जीवन नहीं है। हर व्यक्ति के अंदर क्षमता होती है कि वह ऊंचाइयों तक पहुंचे। बल्कि, यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह हर प्रकार के बंधनों से मुक्त हो और एक आनंदमय जीवन जिए।

तभी हम लोकतंत्र के असली अर्थ को समझ पाएंगे, जिसमें हर व्यक्ति का विकास हो। कोई आगे और कोई पीछे न रहे। सभी आगे बढ़ें। समाज का आखिरी व्यक्ति भी आनंद को प्राप्त करे। हमें पर्यावरण के मूल कारण – अनियंत्रित भोग की समस्या – से मुक्ति पानी होगी। इस मूल कारण को हल करके ही हम खुद को गरीबी से और अपनी धरती मां को विलुप्त होने से बचा सकेंगे।

विमर्श एवं निष्कष

हमें यह भी समझना होगा की क्यों कोई मुद्दे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं तथा अन्य मुद्दे राजनीतिक कैंपेन से बाहर रह जाते हैं। इस संदर्भ में स्टीवन लुक्स का 'पावर एंड एजेंडा सेटिंग' एक महत्वपूर्ण दृष्टिकोण स्थापित करता है।

मुफ्त सुविधाओं का मुद्दा तीनों पार्टियों ने ही बखूबी अपने घोषणापत्र में रखा क्योंकि यह मतदाताओं को रिझाने का एक आसान तरीका था साथ ही इससे कुछ विशेष वर्गों, जैसे कि महिलाएं और गरीबो, को भी फायदा पहुंचाकर एक समूचे वर्ग का मत हासिल करना आसान हो जाता है। इसी कारण फ्रीवीज का मुद्दा मुख्य रूप से चुनावों में उभर कर आया।

वहीं दूसरी ओर, प्रदूषण का मुद्दा किसी भी राजनीतिक दल ने पूर्ण रूप से नहीं उठाया क्योंकि वे जानते हैं की ज्यादातर मतदाता जो कि गरीब हैं और प्रदूषण के दुष्प्रभावों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं रखते हैं साथ ही उनका पूरा ध्यान अपनी मूलभूत जरूरतें ही प्री करने में रह जाता है इसलिए प्रदूषण का मुद्दा उनके लिए बहुत मायने नहीं रखता। इसीलिए , प्रदूषण का मुद्दा उठाकर उनका कोई राजनीतिक फायदा नहीं होने वाला है वहीं दूसरी ओर मुफ्त सुविधाओं का वादा करके उन्हें आसानी से मत मिल सकते हैं।

तो हम यह कह सकते हैं कि दिल्ली के चुनाव में राजनीतिक दलों ने वही मुद्दे उठाए जो कि उन्हें वोट दिलाने का ज्यादा अवसर प्रदान करते हैं न कि जो दिल्ली का सही मायनों में विकास करते हैं और साथ ही हम यह भी कह सकते हैं की चुनाव में कौन से मुद्दे मुख्य होंगे यह राजनीतिक दल ही मुख्य रूप से तय करते हैं ना की जनता, जो राजनीतिक दलों द्वारा तय किए गए मुद्दों पर अपने मत रखती है।

अंततः हम कह सकते हैं कि दिल्ली चुनाव ने हमें लोकतंत्र की शक्ति दिखाई, लेकिन यह भी दर्शाया कि कुछ गंभीर मुद्दे जनता के बीच प्राथमिकता नहीं बन पाए। जलवायु परिवर्तन, गरीबी और मुफ्त सुविधाओं पर एक नई सोच विकसित करने की आवश्यकता है, ताकि हमारा लोकतंत्र वास्तविक रूप से सबके लिए फायदेमंद बन सके।

संदर्भ सूची

- Lukes, Steven. (1974). Power: A Radical View. Palgrave Macmillan.
- https://indianexpress.com/article/opinion/columns/yogendra-yadav-writes-ahead-of-polls-lets-talk-about-the-real-problem-in-delhi-9802524/
- https://www.bjp.org/files/election-manifesto-documents/Delhi-Manifesto_25-01-2025_English_0.pdf
- https://inc.in/delhi-manifesto
- https://data.opencity.in/dataset/delhi-assembly-elections-2025-manifestos/resource/aam-aadmi-party-hindi

♦♦♦♦♦

Aiming High, Touching Sky

सी जी एस

वैश्विक अध्ययन केंद्र

(पूर्वकालिक विकासशील राज्य शोध केंद्र)

अकादमिक अनुसंधान केंद्र भवन

गुरु तेग बहादुर मार्ग

दिल्ली विश्वविद्यालय

दिल्ली– 110007

www.cgs.du.ac.in @cgsofficialdu office@cgs.du.ac.in +91-11-27666281